● वर्ष-3
● अंक-263
रायपुर, गुरुवार
13 जून 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› मन पर लगाएं लगाम सफलता होगी...

खुदरा महंगाई दर निचले स्तर पर

4.75 प्रतिशत पर पहुंचा आंकड़ा

नई दिल्ली। देश की खुदरा मुद्रास्फीति मई में सालाना आधार पर घटकर 12 महीने के निचले स्तर 4.75 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह पिछले महीने यानी अप्रैल में 11 महीने के निचले स्तर 4.83 प्रतिशत थी। द्य सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 2-6 फीसदी के सहिष्णुता दायरे में बना हुआ है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार क्रमिक आधार पर मुद्रास्फीति की दर मई में 0.48 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही।

सरकार के आंकड़ों के अनुसार खाने-पीने की कीमतें कम हुईं= मई में खाद्य मुद्रास्फीति की दर अप्रैल के 8.75 प्रतिशत से घटकर मई में 8.62 प्रतिशत हो गई। हालांकि यह आंकड़ा मई 2023 की खाद्य महंगाई दर 3.3 प्रतिशत से अधिक है। ग्रामीण मुद्रास्फीति मई में घटकर 5.28 प्रतिशत रह गई, जो पहले 5.43 प्रतिशत थी। इस बीच, मई में शहरी मुद्रास्फीति की दर 4.15 प्रतिशत रही।

जून की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के फैसलों के बारे में बताते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि भारत की मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्रीय बैंक चाहता है कि यह प्रक्रिया क्रमिक हो और टिकाऊ आधार पर हो। एमपीसी की बैठक के बाद दास ने मुद्रास्फीति को हाथी बताया था और कहा था कि जून की बैठक के दौरान यह बहुत धीरे-धीरे जंगल में लौटता दिखा।

उस दौरान, अपने अनुमानों में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति के लक्ष्य को 4.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित छोड़ दिया था। वित्त वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर केंद्रीय बैंक के पूर्वानुमान के अनुरूप 5.4 प्रतिशत थी।

अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक घटकर 5% रह गई- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अप्रैल में घटकर 5 प्रतिशत रह गई, जो तीन महीने का निचला स्तर है। मार्च में यह 5.4 प्रतिशत थी। सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि अप्रैल 2023 में आईआईपी वृद्धि दर 4.6 प्रतिशत दर्ज की गई। आईआईपी का पिछला उच्चतम स्तर अक्टूबर 2023 में 11.9 प्रतिशत दर्ज किया गया था, यह नवंबर में घटकर 2.5 प्रतिशत, दिसंबर में 4.2 प्रतिशत और जनवरी 2024 में 4.1 प्रतिशत दर्ज किया गया।

जनवरी 2024 से मई 2024 तक के खुदरा महंगाई के आंकड़े

कब जारी हुए (कब के आंकड़े)	महंगाई दर	पूर्वानुमान	पिछले महीने की दर
जून 2024 (मई)	4.75%	4.90%	4.83%
मई 2024, (अप्रैल)	4.83%	4.80%	4.85%
अप्रैल 2024 (मार्च)	4.85%	4.91%	5.09%
मार्च 2024 (फरवरी)	5.09%	5.02%	5.10%
फरवरी 2024 (जनवरी)	5.10%	5.09%	5.69%

फल और सब्जियों की कीमतों में मामूली कमी

फलों और सब्जियों की मुद्रास्फीति अप्रैल के 27.8 प्रतिशत से घटकर मई में सालाना आधार पर 27.3 प्रतिशत पर आ गई। अनाज और दालों की कीमतें जो भारत के मुख्य आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मुद्रास्फीति की दर क्रमशः 8.69 प्रतिशत और 17.14 प्रतिशत पर आ गई। ईंधन के मामले में मुद्रास्फीति दर मई में घटकर 3.83 प्रतिशत रह गई, जबकि अप्रैल में इसमें 4.24 प्रतिशत की गिरावट आई थी। कपड़े और जूते और हाउसिंग सेक्टर के लिए मुद्रास्फीति दर मई में क्रमशः 2.74 प्रतिशत और 2.56 प्रतिशत रही।

लाल किले पर हमले के दोषी को होगी फांसी

लश्कर आतंकवादी मोहम्मद आरिफ की दया याचिका राष्ट्रपति मुर्मू ने की खारिज

नई दिल्ली। करीब 24 साल पुराने लाल किला हमला मामले में दोषी पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की दया याचिका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खारिज कर दी है। 25 जुलाई, 2022 को राष्ट्रपति पद संभालने के बाद राष्ट्रपति द्वारा खारिज की गई यह दूसरी दया याचिका है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर, 2022 को आरिफ की समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें मामले में उसे दी गई मौत की सजा की पुष्टि की गई थी। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि मौत की सजा पाने वाला दोषी अभी भी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत लंबी देरी के आधार पर अपनी सजा कम करने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अधिकारियों ने राष्ट्रपति सचिवालय के 29 मई के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि 15 मई को प्राप्त आरिफ की दया याचिका 27 मई को खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि आरिफ के पक्ष में कोई राहत देने वाली परिस्थितियां नहीं थीं और इस बात पर जोर दिया कि लाल किले पर हमला देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए सीधा खतरा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सितंबर 2007 में ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि की थी। इसके बाद आरिफ ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने अगस्त 2011 में भी उसे दी गई मौत की सजा देने के आदेश का समर्थन किया था। बाद में उनकी समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ के सामने आई, जिसने अगस्त 2012 में इसे खारिज कर दिया। जनवरी 2014 में एक सुधारात्मक याचिका भी खारिज कर दी गई। उसके बाद, आरिफ ने एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि इससे उत्पन्न होने वाले मामलों में समीक्षा याचिकाएं दायर की गईं।

लाल किला अटैक केस क्या है

आरिफ को हमले को अंजाम देने के लिए अन्य आतंकवादियों के साथ साजिश रचने का दोषी पाया गया, ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2005 में उसे मौत की सजा सुनाई। दिल्ली उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने बाद की अपीलों में फैसले को बरकरार रखा। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि लाल किले पर हमले की साजिश श्रीनगर में दो साजिशकर्ताओं के घर पर रची गई थी, जहां आरिफ ने 1999 में तीन अन्य लश्कर आतंकवादियों के साथ अवैध रूप से प्रवेश किया था। तीन आतंकवादी - अबू शाद, अबू बिलाल और अबू हैदर- जो स्मारक में घुस गए थे, अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए। समीक्षा और उपचारात्मक याचिकाओं सहित कई कानूनी चुनौतियों के बावजूद, आरिफ की दया याचिका खारिज कर दी गई, जो अपराध की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को उजागर करती है।

भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश कर रही पीएफआई : कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2022 में प्रतिबंधित आतंकी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के साथ कथित

संबंधों और सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने के आरोप में महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा गिरफ्तार किए गए तीन लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और श्याम चांडक की खंडपीठ ने अपने अवलोकन में कहा कि आरोपियों ने 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र में बदलने की साजिश रची। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि प्रथम दृष्टया सबूत आरोपियों के खिलाफ थे, अदालत ने रज़ी अहमद खान, उनैस उमर खैय्याम पटेल और कय्यूम अब्दुल शेख की जमानत याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि पहली सूचना रिपोर्ट स्वयं स्पष्ट है। उन्होंने 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश में बदलने की साजिश रची। वे न केवल प्रचारक हैं बल्कि सक्रिय रूप से अपने संगठन (पीएफआई) के विजन 2047 दस्तावेज़ को लागू करने का इरादा रखते हैं। अदालत ने कहा कि आरोपियों ने समान विचारधारा वाले लोगों को भी अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए अपने साथ शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

कुवैत की इमारत में लगी आग, 40 भारतीयों समेत 49 की मौत

कुवैत। कुवैत में एक इमारत में भीषण आग लग गई। एक स्थानीय न्यूज एजेंसी के अनुसार इस हादसे में 49 लोगों की मौत हो गई है। खबर है कि मृतकों में से कई भारतीय भी शामिल हैं। भारतीय दूतावास के अनुसार इस हादसे में 30 से अधिक भारतीय घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह कुवैत के दक्षिणी अहमदी प्रांत के मंगफ इलाके में छह मंजिला इमारत की रसोई में आग लग गई थी। जिस इमारत में यह भीषण आग लगी, उसमें 160 लोग मौजूद थे और सभी एक ही संस्थान में काम करते हैं। बताया गया है कि इन मजदूरों में कई भारत के रहने वाले थे। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने इसे लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। दूतावास का कहना है कि इस अग्निकांड में भारतीयों की मौत के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए +965-65505246 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। दूतावास की तरफ से हर संभव मदद का एलान किया गया है।

मोदी ने शोक प्रकट किया- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में हुए अग्निकांड पर शोक प्रकट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा 'कुवैत में आग की दुर्घटना दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा से आत्मीय मुलाकात हुई। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरूण साव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मंडला के नव निर्वाचित सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद रहे।

प्रमुख समाचार

माझी बने मुख्यमंत्री, दो डिप्टी सीएम ने भी ली शपथ

ओडिशा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मोहन चरण माझी ने बुधवार शाम जनता मैदान में ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में एक भव्य समारोह में ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ ही माझी भगवा पार्टी से पहले मुख्यमंत्री भी बन गए क्योंकि राज्य विधानसभा चुनाव में भारी हार के बाद बीजू जनता दल (बीजेडी) प्रमुख नवीन पटनायक का 24 साल पुराना कार्यकाल समाप्त हो गया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में माझी ने क्योंझर सीट करीब 87,815 वोटों के अंतर से जीती। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र से बीजद की मीना माझी को हराया। भाजपा नेता कनक वर्धन सिंह देव ने ओडिशा के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भाजपा नेता प्रावती परिदा ने भुवनेश्वर में ओडिशा के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल रघुबर दास ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। सुरेश पुजारी, रबीनारायण नाइक, नित्यानंद गोंड और कृष्ण चंद्र पात्रा ने सीएम मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली।

चंद्रबाबू नायडू ने ली आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश में आज नई सरकार की ताजपोशी हो गई। पांच साल बाद राज्य की सत्ता में वापसी करते हुए चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं। नायडू ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हाल के विधानसभा चुनाव में उनकी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने बहुमत हासिल किया है। यह चुनाव उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर लड़ा था जिसमें उन्हें जबरदस्त सफलता मिली है। 2019 में राज्य की सत्ता से बाहर होने के बाद उनके सियासी सफर में कई उतार-चढ़ाव आए। खासकर 2023 में उन्हें कौशल विकास मामले में जेल जाना पड़ा। विधानभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ वह एक बार फिर सत्ता में आ गए हैं। इसके अलावा उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया है और केंद्र की एनडीए सरकार का अहम हिस्सा बनी है। नारा चंद्रबाबू नायडू का जन्म 20 अप्रैल 1950 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के नरवरिपल्ले में एक किसान परिवार में हुआ था। नायडू ने पांचवीं कक्षा तक शेषपुरम के प्राथमिक विद्यालय और 10वीं कक्षा तक चंद्रगिरी सरकारी हाई स्कूल में शिक्षा हासिल की।

पेमा खांडू फिर से बनेंगे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री

नई दिल्ली। राज्य में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में फिर से चुने जाने के बाद पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक और कार्यकाल के लिए तैयार हैं। खांडू सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल केटी परनायक से मिलेंगे। खांडू अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ गुरुवार सुबह शपथ लेंगे, जो राज्य में उनके नेतृत्व की निरंतरता को दर्शाता है। अरुणाचल प्रदेश में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद और तरुण चुघ को पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया था। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू के नेतृत्व वाली भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 60 सदस्यीय विधानसभा में 46 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की। राज्य में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में नेशनल पीपुल्स पार्टी ने पांच सीटें जीतीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने तीन सीटें जीतीं, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने दो सीटें जीतीं, एक कांग्रेस ने और तीन सीटें निर्दलीय ने जीतीं। संगीत के शौकीन पेमा खांडू पिछले कुछ वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, विशेषकर 2016 में पैदा हुए उस संवैधानिक संकट के बाद जिसके कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी गई

रोम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से पहले एक शर्मनाक घटना सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को खालिस्तानी चरमपंथियों ने उद्घाटन के कुछ ही देर बाद ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी गई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक घटनास्थल को तत्काल साफ किया गया। इस मामले को लेकर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, हमने रिपोर्ट्स देखी हैं। भारत ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने का मामला इटली के अधिकारियों के सामने उठाया है। गांधी जी की प्रतिमा को ठीक कर दिया गया है। इस मामले में इटली के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मोदी कल रवाना होंगे। तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा होगी।

आतंकी हमलों के बीच फारूक ने फिर अलापा पाक से बातचीत का राग

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें अभी भी अपने पड़ोसियों के साथ समस्याएं हैं। ये समस्याएं सैन्य कार्रवाई से हल नहीं होंगी... जब तक हम अपने पड़ोसियों से बात नहीं करते, हम इसे हल नहीं कर सकते। सीमाओं के माध्यम से आ रहे हैं और वे आते रहेंगे। कल जो भी सरकार होगी, उसे इसी तरह का सामना करना पड़ेगा। हमें इन स्थितियों से बाहर आने की जरूरत है... हमारी एक बड़ी यात्रा आ रही है (अमरनाथ यात्रा)। देश के बाकी हिस्सों में कोई भी छोटी घटना हो, हमने कभी भी इन चीजों का पक्ष नहीं लिया है। विधानसभा चुनाव पर उनका कहना है, चुनाव तो होंगे ही। जब घटनाएं हुईं तब संसद के लिए भी चुनाव हुआ था. इससे चुनाव नहीं रोका जा सकता। कठुआ के सैदा सुखल गांव के एक सतर्क ग्रामीण ने समय रहते स्थानीय लोगों को हथियारबंद आतंकवादियों को लेकर सचेत कर दिया, जिस कारण एक बड़ी घटना टल गयी और पुलिस को आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिल गयी। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के एक सीमावर्ती गांव में छिपे एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने 15 घंटे से अधिक समय तक चले अभियान में बुधवार को मार गिराया।

राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश बन सकते हैं राहुल गांधी के लिए चुनौती

उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को झटका देने के बाद, समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय राजनीति में रुख करने का फैसला किया है। यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, जिसे उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीता था, और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने रहने का फैसला किया है, जहां वह हाल के संसदीय चुनाव में विजयी हुए थे। यादव ने यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद भी छोड़ दिया।

2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विजय रथ को रोककर अखिलेश राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर उभरे। उत्तर प्रदेश में झटका, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या 62 से घटकर 2024 के संसदीय चुनाव में 33 हो गई, जिससे भाजपा को लोकसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल करने से रोक दिया गया। सपा 37 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और भाजपा और कांग्रेस के बाद देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पार्टी का वोट शेयर भी बढ़कर 33.38% हो गया, जो 2019 में 18.11% था। इससे पहले, 2004 में जब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, तब सपा ने 35 सीटें जीती थीं।

भाजपा के गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलित समर्थन आधार में सेंध लगाने के लिए, अखिलेश ने पीडीए-पिछड़ा (पिछड़े), दलित और अल्पसाख्यक (मुस्लिम) फॉर्मूले पर काम किया। कांग्रेस के साथ गठबंधन

करके उन्होंने मुसलमानों और यादवों के पारंपरिक समर्थन आधार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वरिष्ठ सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा को मिले जनादेश को राष्ट्रीय संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भाजपा को उसके हिंदुत्व के गढ़ में हराने के लिए सपा ने सभी समुदायों का समर्थन हासिल किया। उन्होंने बीजेपी को झटका देने में इंडिया ब्लॉक की सफलता के लिए पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के करिश्माई व्यक्तित्व को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें गठबंधन ने यूपी में 43 सीटें जीतीं।

राहुल को मिलेगी चुनौती

अखिलेश यादव अगर राष्ट्रीय राजनीति की ओर अपना रुख कर रहे हैं तो इससे राहुल गांधी के लिए कई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी में कांग्रेस के लिए बिग ब्रदर की भूमिका में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की ही वजह से यूपी में कांग्रेस को सफलता मिली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में राहुल से पहले अखिलेश की पकड़ देखने को मिलेगी। अखिलेश ने इंडिया गठबंधन को लेकर भी कई परिपक्व फैसले भी लिए हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन करना और सीटों की सौदेबाजी इसी कड़ी का एक हिस्सा है जहां अखिलेश यादव ने अपनी चतुराई दिखाई है।

यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में मुख्य भूमिका राहुल से ज्यादा प्रियंका गांधी की रही है। ऐसे में यूपी की सफलता का श्रेय ज्यादातर अखिलेश यादव को ही जा रहा है। राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेता के तौर पर देश के सभी हिस्सों में लोकप्रिय है। जबकि अखिलेश यादव गठबंधन के सहयोगियों के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं। ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं से अखिलेश यादव के बेहद आत्मीय संबंध है। ऐसा राहुल गांधी के केस में देखने को नहीं मिलता है। इससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बारगेनिंग पावर गठबंधन के सहयोगियों के साथ कम हो जाती है।

ममता और स्टालिन अखिलेश यादव के बातों को महत्व देते हैं। इसलिए गठबंधन के सहयोगियों में उनका महत्व भी बड़ा है। इसके अलावा संसद में राहुल गांधी के साथ-साथ अखिलेश पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। अखिलेश भी राहुल गांधी की तरह युवा नेता है। वह ओबीसी के बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें सरकार चलाने का अनुभव है। हिंदी भाषी राज्यों में उनकी पकड़ भी मजबूत है। ऐसे में इस मामले में भी वह राहुल गांधी पर भारी पड़ सकते हैं।

क्या बदल जाएंगे कांकेर लोकसभा सीट के परिणाम ?

कांग्रेस ने की 4 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की दोबारा गिनती कराने की मांग

■ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

कांकेर। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कांकेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर बहुत कम वोटों के अंतर से हारे। जिसे लेकर बीरेश ठाकुर ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीरेश ठाकुर ने 4 केंद्रों के ईवीएम बदले जाने के आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर को ज्ञापन सौंपा हैं और चारों केंद्रों के ईवीएम की जांच की मांग की है। जिसमें बालोद विधानसभा के दो, गुंडरदेही के एक और सिहावा विधानसभा के एक केंद्र के ईवीएम की जांच की मांग की गई है।

बिरेश ठाकुर ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि मतदान के बाद जो ईवीएम के नंबर एजेंट को दिए गए थे। मतगणना के दिन वो नंबर बदल कैसे गए इसका जवाब निर्वाचन आयोग को देना होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस ईवीएम पर गड़बड़ी को आशंका हो उसकी जांच करवाई जा सकती है, इसलिए उन्होंने 4 ईवीएम जहां ईवीएम नंबर अलग-अलग रहे है उनके जांच के लिए

आवेदन किया है। बीरेश ठाकुर ने तत्कालीन कांकेर कलेक्टर अभिजीत सिंह पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि 16वें राउंड के बाद 2 घंटे तक मतगणना का कोई अपडेट ही नहीं दिया गया। बीरेश ठाकुर ने कांकेर कलेक्टर के मोबाइल डिटेल जांच करने की भी मांग करते हुए कहा कि उन्हें ऊपर से फोन आने लगे थे। अगर उनके काल डिटेल की जांच की जाए तो सब साबित हो जाएगा।

इसके साथ ही बीरेश ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस को हराने में अहम भूमिका रही है और इसलिए तत्कालीन कलेक्टर को आचार संहिता हटते ही प्रमोशन कर गृह और जेल विभाग का सचिव बनाया गया है। आपको बता दें कि कांकेर लोकसभा सीट से भाजपा ने भोजराज नाग को उम्मीदवार बनाया था और कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव में भोजराज नाग को 5 लाख 97 हजार 624 वोट मिले और बीरेश ठाकुर 5 लाख 95 हजार 740 वोट मिले। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग 1884 वोटों से जीतकर सांसद बन गए हैं।

छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही पुरानी योजनाओं पर ग्रहण

कोरबा। कोरबा शहर के निकट वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस में भी महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना हुई थी। यह महापौर राजकिशोर प्रसाद का वार्ड है। प्लान था कि इसके माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जाए। महिला समूह के साथ ही छोटे उद्यमियों को यहां से बढ़ावा मिले। छोटे उत्पादो की सीधे मैन्युफैक्करिंग इकाई लगाई जाए। यह केंद्र आजीविका केंद्र की तरह संचालित हो। जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।लेकिन भूपेश सरकार के जाने के बाद इंडस्ट्रियल पार्क का बुरा हाल है। पंप हाउस के इंडस्ट्रियल पार्क की मशीन जंग खा रही है। इसी तरह ना सिर्फ कोरबा बल्कि प्रदेश भर में कहीं गोबर पेंट बनकर डंप पड़े हुए हैं।तो कहीं इसकी मशीनों को जंग लग रहा है। बताया जा रहा है कि डेवलेपमेंट के लिए सरकार ने राशि रोक दी है। स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बात करने पर जानकारी मिली कि आगे के काम के लिए फंड जारी नहीं हो रहा।

जल जीवन मिशन के तहत समस्या हुई दूर

मारगांव में 12 महीनों पानी के लिए लंबी कतार में खड़ी रहती थी महिलाएं

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजना जल जीवन मिशन के तहत राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम मारगांव के ग्रामवासियों को घर-घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल मिल रहा है। जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव में डिस्ट्रीब्यूशन 1990 मीटर एवं राइजिंग मे1993 मीटर की पाइप लाइन बिछाकर कुल 463 परिवारों को घर में नल से स्वच्छ जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध किया जा रहा है। अब सभी घरों में स्टेफनल कनेक्शन के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो रहा है।

बारिश के दिनों में बाहर से पानी लाने की समस्या, लंबी-लंबी कतार लगकर हैंडपंप तथा कुएँ से पानी भरना, समय अधिक लगने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। गर्मी के दिनों में जल स्तर नीचे चले जाने से कुओं का सूखना, हैण्डपंप बंद होना की

समस्याएं आती थी। जिससे पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था। जल जीवन मिशन आने से गांव के सभी घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। जिससे महिलाओं का समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है। गांव में निवासरत लोगों ने बताया कि प्रत्येक घर को नल और जल से जोड़ने की योजना से गांव का सूखा खत्म हुआ है। गांव के लोगों को पहले काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे पानी भरने के लिए समुचित व्यवस्था न होना, बोरिंग का बंद पड़ जाना, कुओं का सूख जाना जैसी समस्याओं से ग्रामीणों को आये दिन जूझना पड़ता था। पहले ग्रामीणों को पानी भरने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, कई बार रात्रि को पानी के लिए जाना, बरसात के दिनों में पानी के लिए कतार में खड़े रहना पड़ता था। जल जीवन मिशन अंतर्गत गांव के हर घर में टेप कनेक्शन मिलने से आज उनके समय की बचत हो रही है।

कलेक्टर-एसपी की अगुवाई में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक

■ अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

कोरिया। कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगेह और पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था के संबंध में विस्तृत चर्चा की। बैठक में जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने, अप्रिय स्थिति निर्मित न होने, अपराधिक व असामाजिक गतिविधियों पर रोक, धार्मिक वैमनस्यता को रोकने के लिए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

बैठक में कलेक्टर लंगेह ने कहा कि जिले में किसी तरह की अप्रिय घटना होने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना सुनिश्चित करें जिससे समय पर कार्यवाही की जा सकें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज के धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर ,समाज प्रमुखों से सतत सम्पर्क करते हुए समाज प्रमुखों की बैठक ले। कलेक्टर ने धार्मिक स्थलों पर छेड़छाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान पर अनुमति

लेना अनिवार्य होगा।

पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने सूचना के रियल टाइम शेयरिंग के लिए बीट सिस्टम एक्टिव करते हुए बीट स्तर पर जिम्मेदारी तय करने और हर स्तर पर राजस्व और पुलिस अधिकारियों में बेहतर संपर्क और समन्वय की बात पर जोर दिया। एसपी ने बलवा ड्रिल अभ्यास की तैयारी हेतु आर आई को निर्देशित करते हुए बताया कि इस सप्ताह ही इसका संयुक्त अभ्यास किया जाएगा। इसके साथ ही समाज के सभी तबकों से पुलिस मित्र की सूची रखने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में अपर कलेक्टर अरुण कुमार मरकाम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर बैकुंठपुर एसडीएम अंकिता सोम, उप पुलिस अधीक्षक कविता ठाकुर, राजस्व व पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे।

ग्रामीणों के बीच पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, संवाद कर जानी समस्याएं

जगदलपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक जगदलपुर किरण देव ने मंगलवार को शाम नगरनार मंडल के ग्राम मारकेल एवं माड़पाल का दौरा किया। ग्रामीणों से भेंट मुलाकात कर

उनकी समस्याओं से अवगत हुए साथ ही मेला मंडई में भी शामिल होकर ग्राम देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख एवं समृद्धि की कामना किया।

मारकेल एवं माड़पाल क्षेत्र के ग्रामीणों से सीधे संवाद में सामने आयी, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के अविलंब निराकरण के निर्देश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मौके पर दिये, वही संबंधित जनप्रतिनिधि एवं जनता ने क्षेत्र के विकास के संबंध में विधायक के समक्ष अपनी मांगे रखी ,जिस पर विधायक किरण देव ने उचित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया।

ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का जगह जगह ग्रामीणजनों ने भव्य स्वागत बस्तरिया पारंपरिक रूप से किया, इस मौके पर किरण देव ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी ,छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सुशासन है। बस्तर सहित छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में कोई कमी आने नहीं दी जाएगी ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं एवं मांगों को प्राथमिकता से लेकर दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

दोहरे हत्याकांड़ में शामिल चैन सिंह गागड़े सहित 6 गिरफ्तार

जगदलपुर। बस्तर जिला मुख्यालय के नजदीक थाना कोतवाली क्षेत्र अंर्तगत इरिकपाल गांव में जमीन विवाद को लेकर उपजे विवाद में एक दर्जन से अधिक लोगों ने दो भाइयों योगेश कश्यप एवं चन्द्रशेखर कश्यप पिता सम्भुनाथ कश्यप की खेत में मंगलवार को हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड़ में शामिल एक आरोपित चैन सिंह गागड़े को सहित अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर गिरफ्तार हत्या के आरोपियों के नामों का खुलासा नहीं कर रही है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बस्तर जिले के जनपद पंचायत बकावण्ड के ग्राम पंचायत धोबीगुड़ा अंर्तगत ग्राम इरिकपाल बस्तर जिला मुख्यलय जगदलपुर से लगभग 05 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । इस क्षेत्र में आदिवासी, हल्बा, भतरा, महारा, ठाकुर जनजाति के लोग निवास करते है । वर्ष 1992 में ग्राम पंचायत धोबीगुड़ा के गांव ईरिकपाल में हल्बा जाति परिवार के आरोपित चैन सिंह गागड़े के पिरजनों से 5 एकड़ जमीन को आदिवासी

परिवार के शम्भुनाथ कश्यप ने खरीदा था जिसके बाद से सम्भुनाथ कश्यप का परिवार बरसो से उस जमीन पर खेती करते आ रहा है।

पिछले 10 वर्षो से हल्बा परिवार आरोपित चैन सिंह गागड़े के परिजनों की नजर उनके पूर्वजों द्वारा विक्रय की गई जमीन पर नजर गढ़ी हुई थी। जिसका विवाद तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर में इनकी पेशी चलती आ रही, जिसके बाद शासन द्वारा उसके पक्ष में शम्भुनाथ को स्वामित्व के रूप में माना गया। जिसके बाद 11 जून 2024 को सम्भुनाथ के दो पुत्र जिसमें बड़ा पुत्र योगेश कश्यप उम्र 29 वर्ष, छोटा पुत्र चन्द्रशेखर कश्यप उम्र 24 वर्ष ने अपने खेत में कृषि विभाग से किराये पर शासकीय टैक्टर से धान की बोआई कर रहे थे, बोआई के दौरान कुछ ही समय पर चैनसिंह के परिवार के लोगों ने आक्रोशित होकर जमीन को लेकर दोनों भाईयों से कहां-सुनी करने लगे, कहां-सुनी इतनी बड़ गई कि निहत्ते खेत में काम कर रहे दोनों भाईयों को चैनसिंह परिवार से लगभग दर्जन भर लोगों ने अपने साथ लाये टंगिया, फरसा एवं तेज धार-धार हथियार से दोनो भाईयों को मौत के घाट उतारा दिया।

इस दोहरे हत्याकांड़ की सूचना ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को दी गई जिसके बाद थाना कोतवाली द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए इस घटना को संज्ञान में लेकर पुलिस बल सहित घटनास्थल पर पहुंचकर मौका-मुआयना कर पंचनामा की कार्यवही के बाद मृतक दोनो भाई योगेश एवं चंद्रशेखर के शव को पोस्टमाटम के लिए डिमरापाल मेडिकल कॉलेज भेजा गया तथा गांव को छावनी में तब्दील की गई। वहीं पुलिस के द्वारा टीम गठित कर फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

अनहोनी से पहले ही पुलिस ने अर्बन नेटवर्क की तोड़ी कमर

सुकमा। बस्तर में पुलिस अब नक्सलियों के खिलाफ आरपार की लड़ाई लड़ रही है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर नक्सलियों के सप्लायर को पुलिस ने दबोचा है। पुलिस को मुखबिर से नक्सली सामग्री सप्लाई करने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर दोरनापाल थाने से टीम को रवाना करके देवरपल्ली में एमसीपी की कार्रवाई 9 जून को शुरू की गई। इसी बीच कार्रवाई के दौरान जंगल में एक संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी करके दबोचा गया।जिसकी तलाशी लेने पर पुलिस हक्की बक्की रह गई। जिस व्यक्ति को सर्चिंग टीम ने दबोचा उसके पास एक प्लास्टिक की बोरी थी। जिसमें 2 बंडल बिजली वायर, 05 नग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 5 मीटर कोडेक्स वायर, 20 नग जिलेटिन रॉड, 10 नग पोलिबियांन इंजेक्शन, 07 नग न्यूरोबियांन इंजेक्शन, कॉटन पट्टी 1 पैकेट, ग्लूकोज बॉटल 5 नग, ड्रिप 5 नग, सिरिंज 10 नग, सिट्रीजन टैबलेट 10 पत्ता, नक्सली साहित्य 4 नग, पर्चा पाम्पलेट और लाल रंग के कपड़े में बने नक्सली बैनर को बरामद किया। जिसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया गया।

छत्तीसगढ़ में अब पर्यटकों को मिलेगा क्रूज का आनंद

कोरिया । जिले के झुमका बांध में पर्यटक शिकारा बोट के साथ ही अब हाउसबोट या कहें तो क्रूज की सुविधा का भी आनंद ले सकेंगे। झुमका को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने योजना तैयार की है। सीएम विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद यहां पर्यटकों के लिए सुविधाएं जुटाने को लेकर प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने बीते 1 फरवरी को झुमका बांध में 5 शिकारा बोट की शुरूआत की थी। इस दौरान सीएम ने झुमका और सोनहत के घुनघुट्टा जलाशय को पर्यटक क्षेत्र बनाने की घोषणा की थी। जिसके बाद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की विशेष पहल पर झुमका में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए यहां क्रूज और हाउस बोट लाई गई है। झुमका तट पर हाउस बोट का निर्माण हैदराबाद के कारिगर कर रहे हैं। बोट बना रहे कारिगरों ने अगले पिकनिक सीजन में बोट सर्विस शुरु होने की उम्मीद जताई है। आसिफ खान ने कहा करीब डेढ़ से दो महीने में निर्माण पूरा हो जाएगा।

नौ अगस्त को शिक्षक-पालक बैठक कराने का आदेश

कबीरधाम। प्रदेश में पहली बार एक साथ पालक-शिक्षक बैठक होने जा रही है। यह मेगा बैठक 9 अगस्त को होगी। इसे लेकर राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। इस आदेश को लेकर छग सर्व आदिवासी समाज व छग अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ ने विरोध दर्ज कराया है। इसे लेकर कलेक्टोरेट में समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया। समाज के डॉ.संतोष धुर्वे, गजराज टेकाम, आसकरण सिंह धुर्वे ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य है। हर साल 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है व शासन द्वारा सामान्य अवकाश घोषित किया है। इस दिन आदिवासी समाज के सभी वर्ग के लोग अपनी आदिम संस्कृत -परंपरा का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन, स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर 9 अगस्त के दिन सभी शिक्षण संस्थान में मेगा बैठक कराने निर्देशित किया है जो कि गलत है। यह बैठक किसी अन्य दिन कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है।

पुलिस ने जुए के अड्डे पर की छापेमारी, नकदी की जब्त

दुर्ग। दुर्ग के धमधा थाना क्षेत्र के सोनेसरार बस्ती में शिवनाथ नदी किनारे कई महीने से चल रहे जुए के अड्डे पर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं, उनके पास उनके ताश पत्ती समेत 75 हजार रुपए से भी ज्यादा की नकदी बरामद की है। इसके अलावा 9 बाइक और दो कार बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच एएसपी रिचा मिश्रा ने बताया कि धमधा थाना में जुआ का बड़ा फड़ संचालित किया जा रहा है। जिसके बाद क्राइम ब्रांच और धमधा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने शिवनाथ नदी के किनारे कुछ लोग जुआ खेलते गिरफ्तार किया रहे हैं। वही पुलिस को देखकर जुआरियों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने मौके से सतीश कुमार नवरंग, गजेंद्र साहू, अनिल टंडन, उधो कुमार कुर्रे, सुकालू दास खुटेल, शिव सिंह, जयंत वर्मा, शरद कुमार वैष्णव, मनीष बारले, योगेश साहू, प्रदीप मोटवानी और मेहताब सिंह को गिरफ्तार किया।

आकाशीय बिजली गिरने से 5 महिला समेत 15 मजदूर घायल

मोहला-मानपुर। मानपुर इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से 5 महिला समेत 15 मजदूर झुलस गए, घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई गई, जिन्हें मोहला में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव रिफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मानपुर इलाके के कोलरदंड में मौजूद सरकारी नर्सरी में मजदूर काम कर रहे थे। मंगलवार दोपहर को गरज-चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सभी मजदूर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे। तेज गर्जना के साथ पेड़ में आकाशीय बिजली गिर गई। इससे सभी मजदूर झुलस गए। इस घटना में मोहला विकासखंड के भावसा, साल्हे, डोडरी, घोटिया तथा कोरलदंड निवासी 15 महिला-पुरुष मजदूर झुलस गए। ग्रामीणों की मदद से 112 व अन्य संसाधनों से घायलों को मोहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिन्हें राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया। वहीं जिला प्रशासन ने घायलों के उचित उपचार की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।

पांच साल से नहीं मिली पेंशन, 50 किमी का सफर तय कर पटनम पहुंचे बुजुर्ग

बीजापुर। बीजापुर के ग्राम पंचायत एड़ापल्ली के ईरपागुट्टा गांव के बुजुर्ग वेलादी बीरा और वेलादी हड़मा लड़खड़ाते हुए कदमों से हाथ में लकड़ी थामे दो दिनों से 50 किलोमीटर पैदल और ट्रैक्टर से सफर तय कर पेंशन कि गुहार लगाने ब्लाक मुख्यालय भोपालपटनम पहुचे हैं। उन्हें तकरीबन पांच साल से पेंशन नहीं मिली है।

सरकार कि महत्वपूर्ण योजना वृद्धावस्था पेंशन से वो वंचित है बुजुर्ग ने बताया कि पिछले पांच साल से पेंशन के लिए सचिव से गुहार लगा रहा है लेकिन उसके खाते में पेंशन जमा नहीं हो रही है। अपनी समस्या बताते उन्होंने इससे पहले भी भोपालपटनम आकर पंचायत सचिव से मुलाक़ात कर चले गए सचिव द्वारा जल्द ही खाते में पेंशन आने की बात कहकर भेज देते हैं।

नेशनल पार्क एरिया के एडापल्ली, सेंड्रा, बड़ेकाकलेड इन ग्राम पंचायतों के सैकड़ो लोगों को कई सालों से पेंशन नही मिल रहा है, सेंड्रा में 22, बड़ेकाकलेड़ में 37 और एडापल्ली में 34 हितग्राही है। इन लोगो को कई सालों से पेंशन नही मिल रहा है, और कई हितग्राही ऐसे भी है जिनका नाम भी नही जुड़ा है, आपको बता दे कि ग्रामीण आँचल के लोग ज्यादा बोल और समझ नहीं पाते है और उन्हें जिस तरह से बोला जाये वहीं सुन भी लेते है बुजुर्ग हड़मा नें बताया कि उनका सहारा कोई नहीं है बच्चे उनकी जरुरत पूरी नहीं करते कभी किसी चीज कि जरुरत पड़ी तो बार- बार मांगकर सुनना पड़ता है। शक्कर, चायपत्ती, साबुन जैसी जरुरी चीजों कि जरुरत रहती है।लेकिन उसके लिए पैसे नहीं रहते है।

दो दिन में किया 50 किलोमीटर का सफर तय

ब्लाक मुख्यालय भोपालपटनम से तक़रीबन 50 किमी दूर ईरपागुट्टा के बुजुर्ग दो दिनो का सफर तय कर अपनी समस्या सुनाने यहां आए है। घर से निकलने के बाद उन्होंने एक रात कानलापर्ती गांव मे रूककर दूसरे दिन वहां से फिर निकल गए, कुछ दूर चलने जे बाद वे ट्रैक्टर मे बैठकर भोपालपटनम पहुचे है। उन्होंने बताया कि गांव मे वो अकेले नहीं है उनके साथ और भी ग्रामीण है जिन्हे पेंशन नहीं मिल रहा है।

60 माह से नहीं मिला पेंशन

बुजुर्ग हड़मा नें बताया कि उन्हें 5 साल से पेंशन नहीं मिल रहा है पासबुक देखे तो 2017 के बाद खाते मे लेनदेन कि इंट्री नहीं हुई है। पीड़ित पासबुक आधार कार्ड वोटर आईडी ओरिजल और फोटो कॉपी लेकर घूम रहे है। बुजुर्ग ग्रामीणों ने बताया कि सचिव से मिलने गए थे, उसने कहा है कि अब अगले साल पेंशन मिलेगा।

वही दूसरी ओर ग्राम पंचायत एडापल्ली के सचिव गोटा समैया ने बताया कि उनके पंचायत में कुल 34 हितग्राही है। जिसमे समाजिक सुरक्षा पेंशन के 15, वृद्धावस्था के 01, विधवा पेंशन केव14 और सुखद सहारा पेंशन के 4 हितग्राही है। उन लोगो के खाते केवाईसी नही होने के वजह से दो सालों से पेंशन नही आ रहा है।वही डिप्टी कलेक्टर व प्रभारी जनपद पंचायत भोपालपटनम के सीईओ दिलीप उइके ने कहा है कि नेशनल पार्क एरिया के बड़ेकाकलेड, सेंड्रा व एडापल्ली पंचायतों के कई ग्रामीणों के पास आधार कार्ड नहीं हैं। अभी हम भोपालपटनम में शिविर लगाकर आधारकार्ड बनवा रहे हैं। जिन पात्र लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। उनकी जानकारी लेकर उन्हें तत्काल पेंशन दी जाएगी।

बलरामपुर के तातापानी में मौत बनकर दौड़ी ट्रक

बलरामपुर। तातापानी पुलिस चौकी इलाके में बुधवार को एक तेज रफ्तार ट्रक काल बनकर सड़क पर दौड़ा। बेकाबू ट्रक ने पहले तो एक सवार को अपनी चपेट में लिया जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घबराए ट्रक ड्राइवर ने दोगुनी रफ्तार से ट्रक को भगाया जिससे चार से पांच और लोग गाड़ी की चपेट में आ गए। हादसे में घायल लोगों को जामवंतपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया है। जहां सभी का इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद पकड़े जाने के डर से ट्रक का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस की टीम अब फरार ड्राइवर की तलाश में जुट गई है।

पुलिस के मुताबिक ट्रक रामानुजगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 343 पर तेज रफ्तार से जा रहा था। सुबह दस बजे के करीब ड्राइवर ने हाइवे पर ट्रक के ऊपर से अपना नियंत्रण खो दिया। ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक पर सवार युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक युवक का नाम एजाज अहमद है। एजाज अपने दोस्त के साथ बाइक से रामानुजगंज आया था और वापस अंबिकापुर लौट रहा था।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री से नवनिर्वाचित सांसद महेश कश्यप ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से

बुधवार को यहाँ उनके निवास कार्यालय में बस्तर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद श्री महेश कश्यप ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को उपहार स्वरूप काष्ठ शिल्प से निर्मित भगवान श्री राम की मूर्ति भेंट की। मुख्यमंत्री ने श्री कश्यप को लोकसभा सांसद निर्वाचित होने पर बधाई एवं शुभकामनाएँ दी।

दीपक सोनी नए कलेक्टर और एसपी का जिम्मा विजय अग्रवाल को

रायपुर। बलौदाबाजार की घटना में कहीं न कहीं प्रशासनिक ढिलाई भी नजर आ रही थी जिसके चलते बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकार ने कलेक्टर व एसपी को हटा दिया है। दीपक सोनी होंगे नए कलेक्टर, एसपी का जिम्मा विजय अग्रवाल को सौंपा गया है। मंगलवार रात आदेश भी जारी हो गया। दोनों ही काबिल अफसर माने जाते हैं।

रायगढ़ में पत्रकार घोष पर जानलेवा हमले, कांग्रेस ने की निंदा

रायपुर। रायगढ़ में पत्रकार सत्यजीत घोष के ऊपर हुये कातिलाना हमले की कांग्रेस ने कड़ी निंदा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो गयी है। अपराधी और गुंडे तत्व बेलगाम हो चुके है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया। सरेआम लूट, डकैती, चाकूबाजी, बलात्कार की घटनायें हो रही है। आम आदमी और पत्रकार कोई सुरक्षित नहीं है। बैज ने कहा कि पत्रकार सत्यजीत घोष जो टीवी छत्तीसगढ़ नाऊ के रिपोर्टर के साथ रात के अंधेरे में अज्ञात तत्वों के द्वारा पीछे से उनके सर पर वार कर उन्हें घायल कर दिया गया, जिनका उपचार जिला अस्पताल रायगढ़ में चल रहा है। सत्यजीत घोष अपने पूरे काम निपटाकर रात में अपने घर जाने के लिए घर के पास ही पार्किंग में गाड़ी खड़े कर घर की ओर जा रहे थे तभी अंधेरे का फायदा उठाकर उनके साथ यह घटना को अंजाम दिया गया। कांग्रेस मांग करती है कि अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिये।

रायपुर एवं अटल नगर नवा रायपुर के लिए 12 नवम्बर को अवकाश घोषित

रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन द्वारा रायपुर एवं नवा रायपुर अटल नगर के लिए स्थानीय अवकाश 9 अगस्त 2024 के स्थान पर 12 नवंबर 2024 को घोषित की गई है। इस आशय का संशोधन आदेश 10 जून 2024 को जारी कर दिया गया है। कलैण्डर वर्ष में 03 स्थानीय अवकाश की घोषणा सामान्य पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा की जाती है। किन्तु नवा रायपुर अटल नगर तथा रायपुर शहर के संबंध में यह घोषणा सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन द्वारा की जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 09 अगस्त 2024 को प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूर्व से ही सामान्य अवकाश घोषित है। उल्लेखनीय है कि 09 अगस्त 2024 को पूरे प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अवकाश रहेगा।

शहीदी पर्व पर दशमेश सेवा सोसायटी ने किया शरबत वितरण

रायपुर। सिक्ख धर्म के पांचवें गुरु अरजन

देव का शहीदी पर्व समूचे देश के साथ राजधानी रायपुर में भी बुधवार को मनाया गया। इस अवसर पर सिक्ख समाज की प्रमुख संस्था दशमेश सेवा सोसायटी की ओर से हजारों राहगिरों को छबील ठंडक शरबत का वितरण किया गया। शहर के प्रमुख चौराहे शास्त्री चौक में सुबह 11 बजे गुरु जी के अरदास के बाद ज्ञानी जी के हाथों गर्मी की भारी तपिश के बीच लोगों को ठंडा शरबत व चने का प्रसाद वितरण शुरु हुआ जो कई घंटे तक चला। सिक्ख धर्म के सेवादारों के इस पुनीत कार्य की प्रशंसा करते हुए सतनाम वाहे गुरु का सिमरन कर रहे थे। दशमेश सेवा सोसायटी के अध्यक्ष बाबी होरा ने बताया की करीब दस हजार राहगिरों ने आज प्रसाद ग्रहण किया इस अवसर पर प्रमुख रूप से जसबीर सिंह भाटिया, परविंदर सिंह भाटिया, प्रीतपाल सिंह होरा, सतिंदर सिंह, लवली अरोरा, त्रिलोक सिंह सलूजा, जगजीत सिंह अरोरा, कुलदीप जुनेजा, हरमीत सिंह होरा, हरचरण सिंह साहनी सहित सैकड़ों सेवादारों ने सेवा की।

करोड़ों का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई आरोपियों से ही की जाएगी

■ **बलौदाबाजार हिंसा मामला**

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में 10 जून को हुई हिंसा घटना की समीक्षा की गई है। मामले में समीक्षा के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घटना में हुई करोड़ो के नुकसान की भरपाई दोषियों से करवाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर के जगरगुंडा में सड़क निर्माण को लेकर भी मीडिया से खुशी जाहिर की।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बलौदाबाजार में हुई घटना के पीछे समाज से बाहरी लोगों का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक नहीं यह असामाजिक लोगों का काम है। उन्होंने बताया कि मामले में न्यायिक जांच की घोषणा किए जाने के बाद सतनामी समाज ने संतुष्टि जाहिर की थी।

डिप्टी सीएम ने मामले आगे कहा, कि यह बहुत दुख का विषय है, यह नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के लोग हैं, इसमें बाहरी लोगों का हाथ है। उन्होंने कहा कि इस घटना योजनाबद्ध तरीके से

की गई है। हाथ में पेट्रोल बोतल, डंडे-लाठी के साथ लोग नजर आए हैं। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि 9 दिन और 9 रात मैं भी आंदोलन में बैठा था, लेकिन अंदर नहीं गया क्योंकि हमें अपनी सीमा पता है। लोकतंत्र में एक सीमा होती है, इसके आगे अराजकता होती है। सुंदर बिल्डिंग जला दी, किसी को क्या मिला।।?

डिप्टी सीएम शर्मा ने दो टूक शब्दों में कहा है, कि बलौदाबाजार में की गई आगजनी में करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो इसकी भरपाई आरोपियों से ही की जाएगी। भाजपा की तरफ से मामले में कांग्रेसी नेताओं पर समाज को भड़काने के आरोप को लेकर भी बयान दिया है। उन्होने कहा कि जांच में जिन-जिन लोगों का नाम सामने आएगा, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर के जगरगुंडा में सड़क को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंन कहा, कि सड़क का निर्माण उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करता है। इस सड़क के निर्माण में 15 साल से अधिक समय लगा।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 257 सड़कें हैं जिस पर काम नहीं हुआ। दर्जन भर से अधिक पीडब्ल्यूडी की सड़क पर काम नहीं किया जा रहा था। अब राज्य की भाजपा सरकार ने पीडब्ल्यूडी की 81 और सड़कों को चिन्हांकित किया है। 30 सड़कों पर और सिक्योरिटी देकर काम शुरू किया गया है। यह पहल नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए है।

डिप्टी सीएम के आरोप पर पूर्व मंत्री का पलटवार
कहा- अपना दोष दूसरों पर न थोपे भाजपा

रायपुर। बलौदाबाजार में हुई हिंसक घटना को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं उपमुख्यमंत्री अरूण साव के बयान पर पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार घटनाक्रम पर कांग्रेस की संलिप्तता का जो आरोप लगाया है। भाजपा अपना दोष दूसरों पर थोपने का काम ना करे। आरोप लगाना बेहद शर्मनाक है। सरकारी मशीनरी और सरकार पूरी तरीके से फेल है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है। डहरिया ने आगे कहा कि धरना प्रदर्शन में बीजेपी के कई लोग शामिल थे। उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। आरोपों को समाज बर्दाशत नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी सभी समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। बीजेपी ने ध्यान ही नहीं दिया इसलिए ऐसा हुआ। भाजपा के जनप्रतिनिधि, सरकारी मशीनरी और इंटेलिजेंस कहां थे। सरकार के सभी मंत्री कहां थे, शर्म आनी चाहिए। औरंगजेब के समय में ऐसा नहीं हुआ लेकिन बीजेपी काल में ऐसा हो रहा है। शिवकुमार डहरिया ने कहा कि मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार कर धारा लगाई गई है उसकी जानकारी होनी चाहिए। समाज के लोगों को अगर गिरफ्तार करके रखा गया है तो यह अन्याय है। जांच के बाद गिरफ्तारी करें, फिर कार्रवाई करें। निर्दोष लोगों को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। बलौदाबाजार हिंसा पर कांग्रेस ने जांच समिति का गठन किया है। जांच दल को लेकर पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया ने कहा कि कमेटी के सभी सदस्यों से चर्चा की गई है। घटनास्थल पर जाएंगे चर्चा करेंगे। मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करेंगे। मामले की जांच कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री विभागों की समीक्षा करेंगे, इस पर शिवकुमार डहरिया ने कहा कि मंत्री समीक्षा लगातार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री अगर समीक्षा करें रिजल्ट आए तो देखते हैं। बिना रिजल्ट के समीक्षा कर रहे हैं। अनुभवी लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। अनुभवहीन लोग सरकार चला रहे हैं। अनुभवी नेताओं को दरकिनार किया गया है। सुधरने का समय दिया गया था, 6 महीने सरकार के हो चुके हैं। इतनी समझ आ जानी चाहिए कि सरकार कैसे चलाई जाती है।

गिरफ्तारी देने एसपी दफ्तर पहुंचे पूर्व मंत्री गुरु रूद

कहा- बीजेपी के मंत्री मांगे माफी, नहीं तो करूंगा मानहानि का दावा

रायपुर। बलौदाबाजार में बीते 10 जून को सतनामी समुदाय के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। राज्य सरकार ने मामले में एक्शन लेते हुए जिले के कलेक्टर और स्क्र को हटा दिया गया है। वहीं मामले की जांच के लिए विशेष पुलिस टीम भी गठित की है। हिंसा के पीछे सरकार ने कांग्रेस की राजनीतिक साजिश बताया है। आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस के विधायकों, पूर्व मंत्रियों और नेताओं ने लोगों को भड़काने का काम किया है। सरकार के इस बयान के बाद छत्तीगसगढ़ में भूपेश सरकार के दौरान मंत्री रहे गुरु रूद्र कुमार रायपुर के एसपी दफ्तर गिरफ्तारी देने पहुंचे है।

पूर्व मंत्री गुरु रूद्र ने तीन मंत्रियों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की बात भी कही है। उन्होंने बताया कि तीन-तीन मंत्रियों ने मुझ पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है, इसलिए मैं खुद गिरफ्तारी देने आया हूं। गिरोधपुरी में हमारे समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थल में जैत

खाम को तोड़ा जाता है। इस मामले पर झूठी गिरफ्तारी की जाती है। हम पूरे मामले पर ष्टक्च्ढ्ढ जांच की मांग कर रहे थे। राज्य से लेकर केंद्र तक में उनकी सरकार है। लेकिन फिर भी मामले पर ढिलाई बरती गई है। जिसकी वजह से हिंसा भड़की।

पूर्व मंत्री गुरु रूद्र ने कहा- हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे। हमारा समाज परम पूज्य गुरु घासीदास जी का अनुयायी है। हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते है। हमारे समाज के द्वारा एसी निंदनीय घटना नहीं की जा सकती है। यही सब जांच का विषय है। इस घटना में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता रही। लेकिन सरकार जांच न कर सिर्फ़ राजनीति कर रही है। दोषियों को पकड़ना छोड़ हमारे ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगा रहे है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में जहां भी मेरा समाज मुझे याद करेगा मैं जरुर उस जगह पर जाऊंगा। मैंने वहां भाषण दिया, फिर भी मेरे ऊपर इतना घिनौना आरोप लगाया गया है। जिससे पूरा समाज आहत। हमारी मांग है की तीनों मंत्री हमसे माफ़ी मांगे नहीं तो मानहानि का दावा करूंगा और जब तक मेरी गिरफ्तारी नहीं कर ली जाती है। तब तक एसपी कार्यालय में बैठे रहूंगा।

पूर्व मंत्री गुरु रूद्र के गिरफ़्तारी देने पहुंचने के सवाल पर सिविल लाइन सीएसपी अनुराग झा ने कहा कि एसपी साहब मीटिंग में व्यस्त है। इनका कहना है, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। सभी चीजे प्रक्रिया के तहत की जाती है। कानून के दायरे में रहते हुए पुलिस सारा काम करती है।

छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग द्वारा लाँच किया गया ई-संवीक्षा पोर्टल

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य कर (जीएसटी) विभाग द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नई पहल करते हुए ई-संवीक्षा पोर्टल लाँच किया गया है। यह पोर्टल श्री रजत बंसल, आयुक्त, राज्य कर, छत्तीसगढ़ की पहल पर राज्य कर मुख्यालय, नवा रायपुर के डायरी कक्ष एवं कम्प्यूटर कक्ष द्वारा तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत मैदानी कार्यालयों के समुचित अधिकारियों द्वारा जीएसटी अधिनियम की धारा 61 एवं धारा 73 और/ अथवा धारा 74 के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग आनलाईन की जानी है।

प्रारंभिक चरण में ई-संवीक्षा के अंतर्गत स्क्रूटनी माड्यूल बनकर तैयार है एवं लाईव किया जा चुका है तथा एड्जुडिकेशन माड्यूल तैयार किया जा रहा है। इससे न केवल विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मानिटरिंग की जा सकेगी बल्कि ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक डायरी भी आनलाईन होगी और एनालीटिक्स में इससे प्राप्त होने वाले आँकड़ों का राजस्व हित में उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के व्यापारियों को होने वाली व्यवहारिक परेशानियों का निराकरण करने मे भी ई-संवीक्षा माड्यूल कारगर साबित होगा।

गौरतलब है कि, राज्य कर आयुक्त के ध्यान में कुछ ऐसे प्रकरण आये थे जिनमें एक ही व्यवसायी की एक ही अवधि के प्रकरण में एक से अधिक अधिकारियों द्वारा अलग-अलग समय पर नोटिस जारी किए गये थे, जिसके बाद आयुक्त द्वारा ई-संवीक्षा माड्यूल की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू करवाया गया है।

कृषि मंत्री नेताम ने की खेती किसानी तैयारियों की समीक्षा

गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने मंत्रालय महानदी भवन में संबंधित विभागों के आला अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने खरीफ 2024-25 की तैयारियों की गहन समीक्षा की। मंत्री नेताम ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण खाद, प्रमाणित बीज और अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंत्री नेताम ने कहा कि किसानों को उनकी डिमांड के अनुरूप खाद-बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निरंतर अपने-अपने इलाकों का दौरा कर खाद-बीज के भण्डारण एवं उठाव पर निगरानी रखने के साथ ही इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सैम्पलिंग और जांच पड़ताल जारी रखने के निर्देश दिए।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार ने जानकारी दी कि पिछले खरीफ विपणन वर्ष 2023 में सहकारिता क्षेत्र में समग्र रुप से 4.62 लाख क्विंटल बीज का वितरण किया गया था। चालू खरीफ वर्ष 2024 में सहकारी क्षेत्र में 5.44 लाख क्विंटल बीज मांग का आंकलन किया गया है। वर्तमान में बीज निगम के पास कुल 6.31 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध है, जो मांग का 116 प्रतिशत है। 10 जून की स्थिति में कुल 4.16 लाख क्विंटल बीज का भण्डारण विभिन्न सहकारी सोसाटियो में किया गया है, जो मांग लगभग 76 प्रतिशत है। कृषकों द्वारा अभी तक 2.41 लाख क्विंटल बीज का उठाव किया जा चुका है, जो विगत वर्ष की इसी अवधि में हुए उठाव 1.64 लाख क्विंटल की तुलना में 47 प्रतिशत अधिक है। सहकारी क्षेत्र में उर्वरक का वर्तमान भण्डारण 6.20 लाख टन है, जो मांग का 72 प्रतिशत है। कृषकों ने अब तक 3.29 लाख टन खाद का उठाव किया है, जो मांग का 38 प्रतिशत है।

मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि संपूर्ण खरीफ सीजन में भण्डारण की इस गति को बरकरार रखा जाए, ताकि आपूर्ति बाधित न होने पाए। उन्होंने अधिकारियों को भारत सरकार के कृषि एवं रासायन मंत्रालय एवं उर्वरक प्रदाय कंपनियों से निरंतर समन्वय बनाये रखने के निर्देश दिए। उन्होंने नैनो फर्टिलाईजर को बढ़ावा देने, सीमावर्ती जिलों में उर्वरक परिवहन पर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अपेक्स बैंक के अधिकारियों से कहा कि समितियों में भण्डारण क्षमता का आंकलन कर लिया जाए, यदि भण्डारण हेतु अतिरिक्त गोदाम की आवश्यकता हो तो इसका प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराया जाए।

भू-नक्शों के जिओ-रिफ्रेंसिंग से आएगी भूमि विवादों में कमी

■ **मुख्यमंत्री साय की पहल पर राजस्व प्रशासन में नवाचार के लिए तैयार की जा रही रणनीति**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी कुछ दिनों में राजस्व प्रशासन काफी चुस्त-दुरूस्त नजर आएगा। राजस्व प्रशासन में नई-नई तकनीकों के माध्यम से नवाचार करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के मद्देनजर राजस्व प्रशासन में नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस नई तकनीक का नाम जिओ रिफ्रेंसिंग है। इस तकनीक के माध्यम से भूमि के नक्शों के लिए खसरा के स्थान पर यू.एल.पिन नंबर दिया जाएगा। साथ ही भूमिधारक को भू-आधार कार्ड मिलेगा। राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए बजट में 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस नई तकनीक के इस्तेमाल को अपनी मंजूरी दे दी है, इसके लिए बजट में प्रावधान भी कर दिया गया है। जिओ रिफ्रेंसिंग तकनीक के उपयोग के लिए राजस्व से जुड़े अमलों की व्यवस्था के साथ ही इनके प्रशिक्षण के लिए रणनीति बनाई जा रही है। जिओ रिफ्रेंसिंग के काम को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के नवीन पदों का सृजन किया जा रहा है।

जिओ रिफ्रेंसिंग तकनीक में छोटी से छोटी भूमि का लॉन्गीट्यूड और एटीट्यूड के माध्यम से वास्तविक भूमि चिन्हांकित करना आसान हो जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में भूमि संबंधी आने वाली दिक्कतों के मद्देनजर भूमि का नवीन सर्वेक्षण किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में भूमि स्केल का पैमाना 1ः500 रखा जाएगा। इससे नगरीय क्षेत्रों में घनी आबादी होने पर ही छोटे से छोटे भूखण्ड को भू नक्शे में आसानी से दर्ज किया जा सकता है। राजस्व प्रशासन में सुधार की दृष्टि से भूमि के डायवर्सन कराने की प्रक्रिया को भी ऑनलाईन करने की योजना है।

राजस्व संबंधी दिक्कतें लोगों को उनके क्षेत्र में ही सुलझाने के लिए नये स्थानों परं उप तहसील कार्यालय शुरू करने के भी पहल की जा रही है। इसी प्रकार नवगठित अनुविभागों में भी तहसील कार्यालय शुरू होंगे। राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने मुंगेली जिले के चकरभाठा और बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के सकर्रा में उप तहसील कार्यालय शुरू करने की घोषणा की गई है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरू करने के भी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

श्रमिकों के बुढ़ापे की चिंता हुई दूर

श्रमिकों की पेंशन हुई जारी

■ **60 वर्ष पूर्ण कर चुके आठ और श्रमिकों के पेंशन पर श्रम मंत्री के निर्देश पर पेंशन जारी**

रायपुर। प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रमिक पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष पूर्ण कर चुके आठ और श्रमिकों के पेंशन को श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने निर्देश पर जारी किए गए। श्रमिकों के हित और उनके बेहतर जीवन यापन के लिए छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिकों के पेंशन योजना की शुरूआत 29 मार्च को की गई थी। इस योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को पेंशन राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा रही है। इसके अलावा भी कई सारे लाभ मिलेंगे।

बुधवार को श्रम मंत्री और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष लखन लाल देवांगन ने आठ और श्रमिकों का पेंशन जारी किया। इस अवसर पर मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव सरकार श्रमिकों की हितेषी है। सरकार की पूरी मंशा है की श्रमिकों को योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। श्रमिकों के हित एवं उनके बेहतर जीवन यापन के लिए निर्माण

श्रमिकों के पेंशन योजना का लाभ श्रमिको को दिया जा रहा है। जिसमें पात्र निर्माण श्रमिकों को पेंशन राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। इस योजना के तहत् ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 साल पूरी चुकी है, उन श्रमिकों को हर महीने 1500 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। अगर पेंशनधारी निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो निर्माण श्रमिक के आश्रित (पति/पत्नी) को 750 रूपए मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इन जिलों के श्रमिकों को राशि हुई जारी महासमुंद के 2 श्रमिक, बेमेतरा के 4 श्रमिकों को, राजनांदगांव और दुर्ग के एक-एक श्रमिक को पेंशन जारी किया गया है।

ओडिशा में सुभद्रा योजना का मिला भाजपा को लाभ : मुख्यमंत्री

■ **सीएम साय बोले- भाजपा जो कहती है, उसे पूरा करती है**

रायपुर। ओडिशा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 78 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल कर सत्ता में आई है। जिस तरह छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 में बीजेपी को महतारी वंदन योजना का लाभ मिला, उसी तरह ओडिशा में भी बीजेपी को सुभद्रा योजना का लाभ मिला है। ओडिशा में बीजेपी की इस बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी जो कहती है, उसे पूरा करती है।

दरअसल, ओडिशा के नए

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रवाना हुए। रवानगी से पहले सीएम साय ने रायपुर एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान सीएम साय ने बताया कि मेरे साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधायक पुरंदर मिश्रा भी ओडिशा जा रहें है। छत्तीसगढ़ के नेताओं और मंत्रियों का सहयोग ओडिशा के चुनाव में रहा है। ओडिशा की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री पर और मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। पहली बार ओडिशा में भाजपा की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना की तरह ओडिशा में भी पार्टी को सुभद्रा योजना का लाभ चुनाव में मिला, इस सवाल पर सीएम साय ने कहा कि बिल्कुल ओडिशा में भी जो वहां का चुनावी घोषणा पत्र है। वह छत्तीसगढ़ की भाती है। हमने 100 दिन में छत्तीसगढ़ में जो काम किया, उसका असर ओडिशा पर भी दिखा है। भाजपा जो कहती है, उसे पूरा करती है।

कार्यालय कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

सार्वजनिक सूचना

कमांक/279/भू-अर्जन/2024 — रायपुर, दिनांक 29/05/2024

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), विधानसभा संभाग रायपुर द्वारा हथबंद-सिलपट्टी-निनवा मार्ग का निर्माण हेतु ग्राम सिलपट्टी की भूमि कुल खसरा 01 कुल रकबा 1080 वर्गमीटर भूमि को आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत् निम्नलिखित भूमि स्वामी की उनके नाम के समक्ष अंकित ग्राम सिलपट्टी, तहसील तिल्दा-नेवरा की निजी भूमि कय किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। संबंधित भूमि स्वामियों से प्रारूप ख में भूमि विक्रय करने के संबंध में स्वीकृति प्राप्त किया जा चुका है-

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता/पति का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (व. मी. में)
1	2	3	4
1	श्री रामसाय पिता श्री शिवबगस सतनामी ग्राम सिलपट्टी	368/1	1080

उक्त सार्वजनिक सूचना पर यदि किसी व्यक्ति/संस्था को उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार की स्वत्व संबंधी आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन की तिथी से 15 दिवस तक लिखित आपत्ती कार्यालय कलेक्टर, रायपुर में प्रस्तुत कर सकते है। 15 दिवस के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

कलेक्टर
रायपुर (छत्तीसगढ़)

जी- 242500223/3

चंडीगढ़ की घटना : भविष्य के लिए एक चुनौती

चन्द्र शेखर गंगराड़े

चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर दिनांक 6 जून, 2024 को मंडी संसदीय क्षेत्र की नवनिर्वाचित सांसद सुश्री कंगना रनौत के साथ जो घटना घटित हुई उसकी जितनी निंदा की जाये वह कम है और वह इसलिए कि जिनके हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी है वे ही यदि आवेश में आकर इस प्रकार के कृत्य करते हैं तो उसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता और इसके कारण न केवल उस संस्था की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है जिसमें वे पदस्थ होते हैं बल्कि उस समूची बिरादरी पर भी उसकी आंच आती है, जिसकी वह सदस्य है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस घटना की निंदा करने के बजाए उस तथाकथित संगठन के नेता उस महिला कांस्टेबल की प्रशंसा कर रहे हैं जिसने यह कायराना कृत्य किया है और उसे न केवल नगद राशि से पुरस्कृत कर रहे हैं बल्कि उसे महिमामंडित भी कर रहे हैं। इस सब के जरिये हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देने जा रहे हैं क्या यही हमारे संस्कार हैं। सुश्री कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के संबंध में क्या टिप्पणी की थी यहां अब वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं है हालांकि सुश्री कंगना रनौत ने अपना वह ट्वीट डिलीट भी कर दिया था लेकिन क्या यदि हम किसी के विचारों से सहमत नहीं हैं तो उसका प्रतिकार इस प्रकार किया जाना उचित है निश्चित रूप से नहीं, और यदि इस प्रकार कोई भी व्यक्ति, यदि किसी के विचारों से सहमत नहीं है और वह अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए इस प्रकार प्रतिकार करने लगेगा तो यह अराजकता ही कहलायेगा और इसका कोई अंत नहीं होगा। इस घटना से स्वाभाविक रूप से वर्ष 1984 की याद ताजा हो गई, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सुरक्षाकर्मियों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण अपनी ही प्रधानमंत्री को गोलियों से भून दिया था जबकि उनका कर्तव्य प्रधानमंत्री की रक्षा करना था और यदि इस प्रकार जिनका काम सुरक्षा करना है उनका ही आचरण संदिग्ध होने लगेगा तो समूचे सुरक्षा-तंत्र की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ जायेगी। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरा यह मानना है कि ऐसे कृत्यों को हतोत्साहित करना चाहिए न कि उसे महिमामंडित किया जाये। उक्त घटना के परिप्रेक्ष्य में अब सुरक्षा बलों को भी इस बात की समीक्षा करनी होगी कि इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों को संवेदनशील क्षेत्रों में पदस्थ नहीं करना चाहिए। अन्यथा भविष्य में स्थिति और भयावह हो सकती है। इस घटना का और भी हैरान करने वाला, दूसरा पहलू यह है कि कांस्टेबल के पक्ष में तो काफी लोग खड़े हो गये हैं और उस पर इनामों की बारिश कर रहे हैं, वहीं उक्त घटना की निंदा या उसके विरोध में कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। यहां तक कि बॉलीवुड भी, जो हमेशा ऐसी घटनाओं पर मुखर रहता है, वह भी मौन है। ऐसी घटनाओं पर मौन रह कर हम क्या संदेश देना चाहते हैं कई बार मौन रहना भी अपराधी के पक्ष में बोलने की श्रेणी में हमें खड़ा करता है और यदि हम ऐसी घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो भविष्य में उसके बहुत ही दूरगामी एवं भयावह परिणाम होंगे, जो हम सभी के नियंत्रण के बाहर रहेंगे।

मोदी ने टीम-72 से क्या-क्या साधा

अभिनय आकाश

देश में नई सरकार का गठन हो चुका है। 30 सांसदों ने कैबिनेट, 5 सांसदों ने स्वतंत्र प्रभार और 36 सांसदों ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। जैसा पिछली सरकार में अमित शाह के पास गृह मंत्रालय था, राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था। निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय था। एस जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय था। राष्ट्रीय हित और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अहम फैसले लेने वाली सुरक्षा मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) से जुड़े रक्षा, गृह, विदेश और वित्त मंत्रालयों के चेहरों को इस बार भी रिपीट मोड में रखा गया है। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको याद हो कि 2009 से 2014 के यूपीए कार्यकाल के दौरान भी कांग्रेस ने इन चारों अहम मंत्रालय को अपने पास ही रखा था।

इससे पहले कि हम इस बात पर गहराई से विचार करें कि मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ कैसे संतुलन बनाया है, आइए इस पर बेहतर नज़र डालें कि किसे क्या मिला है। मोदी ने राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, अमित शाह को गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री और एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाए रखा है। उन्हें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया है, जबकि हरियाणा के एमएल खट्टर को बिजली मंत्रालय के साथ आवास और शहरी मामले दिए गए हैं। शिक्षा, रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग सहित प्रमुख विभाग भी भाजपा ने अपने पास रखे हैं। पिछले कार्यकाल के लगभग 15 मंत्रियों ने राव इंद्रजीत सिंह (सांख्यिकी, योजना) जितेंद्र सिंह (विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पीएमओ में राज्य मंत्री, कार्मिक, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष); अर्जुन राम मेघवाल (कानून और संसदीय कार्य राज्य मंत्री) सहित अपने विभागों को बरकरार रखा है। हालाँकि, अपने सहयोगियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मोदी ने टीडीपी और जेडी (यू) को भी कुछ प्रमुख विभाग सौंपे हैं। उदाहरण के लिए, पीएम मोदी ने युवा टीडीपी मंत्री के राम मोहन नायडू को प्रमुख नागरिक उड्डयन विभाग आवंटित किया है। जद (यू) के राजीव रंजन ललन सिंह को पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मिला है। चिराग पासवान अपने दिवंगत पिता राम विलास पासवान के नक्शेकदम पर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में बने रहेंगे। इसके अलावा, कर्नाटक स्थित जनता दल-सेक्युलर के एचडी कुमारस्वामी को इस्पात मंत्रालय दिया गया है, जबकि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मिला है।

संविधान के अनुच्छेद 74 में इस बात का जिक्र है कि सरकार चलाने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। मंत्रिपरिषद का काम राष्ट्रपति की सहायता करना और उन्हें सलाह देना होता है। अनुच्छेद 74 कहता है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जा सकती है। मंत्री बनने के लिए व्यक्ति को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगर वो सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है।

अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, वेतन भत्ते से जुड़ी चीजों का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले ये प्रावधान नहीं था। लेकिन साल 2003 में 91वें संशोधन के जरिए ये अधिनियम जोड़ दिया गया। मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। उनके बाद संसद का बंटवारा तीन श्रेणियों में मुख्यतः किया गया है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। हालांकि अब उप मंत्री का पद देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी उप प्रधानमंत्री भी देखने को इतिहास में मिला है।

मंत्रालयों का आवंटन केवल निरंतरता को ही नहीं दर्शाता है। इसके निहितार्थ 2025 में विधानसभा चुनावों से भी जुड़े हैं। साल के अंत में छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों - हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और बिहार में चुनाव होंगे। अगले साल की शुरुआत में पूर्वोत्तर में असम में भी चुनाव होंगे। वैसे तो बिहार का कार्यकाल 2025 तक का है। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से इसी वर्ष चुनाव कराने पर जोर है। इसलिए भी इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले बिहार राज्य को मंत्रिमंडल में बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। राज्य के लोगों को चिराग पासवान (लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास), गिरिराज सिंह (भाजपा), जीतन राम मांझी (हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा), रामनाथ ठाकुर (जेडीयू), ललन सिंह (जेडीयू), नित्यानंद राय (बीजेपी), राज भूषण चौधरी (बीजेपी), सतीश दुबे (बीजेपी के रूप में आठ बर्थ दी गई हैं। बीजेपी के इस मंत्रालय बंटवारे में जातिय समीकरण पर भी फोकस रखा गया है। वास्तव में भाजपा की पसंद दो उच्च जातियों (गिरिराज सिंह और सतीश दुबे), एक ओबीसी (नित्यानंद राय) और एक ईबीसी (राज भूषण चौधरी) के साथ जातियों के सावधानीपूर्वक मिश्रण को दर्शाती है। दरअसल, राजनीति में नौसिखिया और पेशे से डॉक्टर राज भूषण चौधरी मुजफ्फरपुर की निषाद बहुल सीट पर मल्लाह समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, जिन्हें अभी भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक माना जाता है। महाराष्ट्र एक और राज्य है जहां इस साल चुनाव होंगे है। राज्य में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन से कमतर प्रदर्शन को देखते हुए, पार्टी ने इसे कैबिनेट में बेहतर प्रतिनिधित्व देना सुनिश्चित किया है। राज्य को पांच मंत्री मिले हैं, जिनमें भाजपा के कद्दावर नेता नितिन गडकरी भी शामिल हैं। पांच सीटों में से भाजपा ने दो सीटें अपने पास रखी हैं और एक-एक सीट सहयोगी दल शिव सेना और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को दी है। कहा जाता है कि पांचवां एक कनिष्ठ मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अजीत पवार की राकांपा को आवंटित किया गया था। लेकिन सरकार के लिए पार्टी के उम्मीदवार प्रफुल्ल पटेल ने इसे पदावनति बताते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया। गडकरी के अलावा, भाजपा ने एक युवा और प्रमुख ओबीसी चेहरे रक्षा खडसे को खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया है। हरियाणा में भी इसी साल चुनाव होने हैं। प्रदेश के हिस्से तीन मंत्री पद दिए गए हैं। करनाल से जीतने वाले पूर्व भाजपा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आवास और शहरी मामलों का मंत्री और ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह, जिन्हें स्वतंत्र (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया है, और कृष्ण पाल गुर्जर (स्वतंत्र) को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जो चुनाव के लिए पार्टी के इरादे को दर्शाता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, जो 2014 के बाद पहली बार जल्द ही अपने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करेगा, का प्रतिनिधित्व मोदी 3.0 में भाजपा के जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। और दिल्ली, जहां अगले साल की शुरुआत में मतदान होगा। पहली बार सांसद हर्ष मल्होत्रा ??(पूर्वी दिल्ली) और कमलजीत सहरावत (पश्चिमी दिल्ली) को शामिल किया गया है। झारखंड से मंत्रिमंडल को दो मंत्री मिले हैं और दोनों भाजपा से हैं। झारखंड में इस साल चुनाव भी होंगे। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, जबकि संजय सेठ को रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। 2026 में असम में भी चुनाव होंगे और वहां अपना प्रभाव बरकरार रखने की उम्मीद करते हुए भाजपा ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और भाजपा राज्य राज्य मंत्री के रूप में सभा सांसद पबित्रा मार्गेरिटा के रूप में पूर्वोत्तर राज्य से दो मंत्रियों को शामिल किया है। अहोम समुदाय के तीन युवा और प्रभावशाली विपक्षी नेताओं के उदय को विफल करने के लिए मार्गेरिटा को ऊपर उठाया गया है, जो पूर्वी/ऊपरी असम के कई विधानसभा क्षेत्रों में जीत के लिए महत्वपूर्ण है। पोर्टफोलियो आवंटन संदेश को स्पष्ट करता है। हालांकि राष्ट्रीय चुनाव पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में नहीं गए होंगे - वे अपने दम पर 272 का बहुमत का आंकड़ा हासिल करने में असमर्थ रहे - पार्टी अपनी शक्ति को मजबूत करने के प्रयास में विधानसभा चुनावों के लिए पहले से ही खुद को तैयार कर रही है। क्या नेताओं का प्रतिनिधित्व उनके प्रयासों में मदद करेगा, यह तो समय ही बताएगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

सुबालोपनिषद् (भाग-8)

गतांक से आगे...

(इसी प्रकार) चित्त अध्यात्म है, चेतयितव्य (चिन्तन का विषय) अधिभूत है, उसमें क्षेत्रज्ञ अधिदैवत है। नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो चित्त में, चेतयितव्य में, क्षेत्रज्ञ में, नाड़ी में अनन्त है।

(उपर्युक्त की तरह ही) वाक् (वाणी) अध्यात्म है, वक्तव्य अधिभूत है और अग्नि अधिदैवत हैं। नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो वाणी में, वक्तव्य में, अग्नि में, नाड़ी में अनन्त है।

(इसी प्रकार) दोनों हाथ अध्यात्म हैं, ग्रहणीय पदार्थ अधिभूत हैं, इन्द्र अधिदैवत हैं तथा नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो हाथ में, ग्रहण करने के विषय में, इन्द्र में, नाड़ी में अनन्त है।

(इसी तरह) दोनों पैर अध्यात्म हैं, गन्तव्य अधिभूत है, विष्णु अधिदैवत हैं। नाड़ी इनका मूलस्थान है। जो पैर में, गन्तव्य में, विष्णु में, नाड़ी में..अनन्त है। (उपर्युक्त जैसा) पायु (गुदा) अध्यात्म है, विसर्जयितव्य (विसर्जन करने का विषय) अधिभूत है और मृत्यु अधिदैवत है। नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो गुदा में, विसर्जनीय में, मृत्यु में, नाड़ी में...अनन्त है।

इसी प्रकार उपस्थेन्द्रिय अध्यात्म है, आनन्दयितव्य (आनन्द का विषय) अधिभूत है और प्रजापति अधिदैवत हैं। नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो उपस्थ (जननेन्द्रिय) में, जो आनंद के विषय में, जो प्रजापति में, जो नाड़ी में, जो प्राण में, जो विज्ञान में, जो आनन्द में, जो हृदयाकाश में और जो इस सम्पूर्ण शरीर में संचरित होता है, वही यह आत्मा है। इस आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए। यह जरा रहित, भरण रहित, भयरहित, शोकरहित और अनन्त है। यह (तुर्यातिरिक्त) ईश्वर सर्वज्ञ है, यह सर्वेश है, सर्वाधिपति है, अन्तर्यामी है और यही सबका उत्पत्ति स्थान है।

क्रमशः ...

अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरुकता दिवस

शुभम

आज यानी 13 जून को दुनियाभर में 'अंतरराष्ट्रीय ऐल्बिनिज्म (रंगहीनता) जागरूकता दिवस' मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश ऐल्बिनिज्म को लेकर जागरूकता फैलाना है। आज के दिन दुनियाभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर ऐल्बिनिज्म को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। समाज में इस रोग को लेकर कई तरह की गलत धारणा फैली हुई है। इस रोग से ग्रसित लोगों को भेदभाव सहना पड़ता है। जिसके कारण उनका जीवन तनावपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि इस रोग को लेकर फैले तमाम मिथ को रोकने और जागरूकता फैलाने के लिए 'अंतरराष्ट्रीय ऐल्बिनिज्म जागरूकता दिवस' मनाया जाता है।

हेल्थलाइन में छपी एक खबर के मुताबिक ऐल्बिनिज्म या रंगहीनता एक वंशानुगत डिसऑर्डर का एक समूह है, यह रोग त्वचा, आंखों और बालों से संबंधित है। जिसमें पिग्मेंट मेलानिन का बहुत कम या कोई उत्पादन नहीं होता। बॉडी के द्वारा उत्पादित मेलानिन का प्रकार और मात्रा ही त्वचा, बालों और आंखों का रंग निर्धारित करती है। मेलेनिन ऑप्टिक नसों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए ऐल्बिनिज्म से ग्रसित लोगों को दृष्टि संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। मेलानिन की कमी होने पर बाल या त्वचा का रंग सफेद, पीला, हल्का भूरा, हल्का लाल, आंखों का रंग भी हल्का लाल या भूरा हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी त्वचा और आपके बालों को रंग कहां से मिलता है? मेलेनिन नामक एक पिगमेंट, जिसका प्राथमिक कार्य सनस्क्रीन की तरह हानिकारक यूवी विकिरण से आपकी त्वचा की रक्षा करना है। ऐल्बिनिज्म एक अनुवांशिक रोग है। यह पैरेंट्स के जरिए बच्चों को हो सकता है। इसके अलावा, बाल, त्वचा और आंखों को रंग प्रदान करने वाला तत्व मेलानिन जब घटने लगता है, तब यह बीमारी शुरू हो सकती है। अगर किसी के पैरेंट्स को यह बीमारी है तो अनुवांशिक तौर पर उनके बच्चों को भी यह हो सकता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर, 2014 को आयोजित सभा में 13 जून को 'इंटरनेशनल ऐल्बिनिज्म अवेरनेस डे' के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। जिसके बाद 2015 से अंतरराष्ट्रीय ऐल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में ऐल्बिनिज्म को लेकर जागरूकता फैलाना है।

ऐल्बिनिज़्म से पीड़ित लोगों में अकेलापन एक आम स्थिति है। अक्सर ऐसे लोगों के साथ समाज में ख़राब व्यवहार किया जाता है जिन्हें आमतौर पर ऐल्बिनिज़्म के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। लेकिन ऐल्बिनिज़्म वाले लोग अपनी ज़िंदगी में काफी कामयाब होते हैं। ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध लोगों में शामिल हैं, गौरव जैन (इंडियन आइडल फाइनलिस्ट) और प्रशांत नाइक जिन्हें बैंकिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2013 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा रोल मॉडल ऑफ द ईयर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

संविधान और सर्वसम्मति के लिए जनादेश

प्रभु चावला

कुछ लोग हार से तबाह हो जाते हैं और कुछ जीत कर ओछे हो जाते हैं। महानता उसमें होती है, जो हार व जीत को समान भाव से लेता है। प्रतिष्ठित अमेरिकी लेखक जॉन स्टीनबेक ने कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत के हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजे के विश्लेषण के बारे में उनकी टिप्पणी इतनी सटीक साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले ऐसा केवल जवाहरलाल नेहरू ही कर सके थे। यह रिकॉर्ड बनाने वाले वे पहले गैर-कांग्रेसी नेता हैं।

वे अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे संघ प्रचारक भी हैं। फिर भी नेहरू और मोदी में गणित का अंतर है। नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 का चुनाव लगभग दो-तिहाई बहुमत से जीता था, पर भाजपा तीसरी बार अपने दम पर बहुमत नहीं पा सकी और सरकार बनाने के लिए सहयोगियों का साथ लेना पड़ा है। इस जनादेश ने एक पार्टी के बहुमत की सरकार की अवधारणा पर गहरी चोट की है। भारत एक दशक बाद गठबंधन के युग में लौट आया है, जिसकी शुरुआत 1989 में राजीव गांधी की हार के साथ हुई थी। भाजपा ने 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटें जीती थीं। इस बार भाजपा लगभग 430 सीटों पर लड़ी थी, पर उसे 240 सीटें ही मिल सकीं। उसने 63 सीटें खो दीं, जिनमें अधिकांश उसके पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के खाते में गईं।

इस बार यह मोदी 3.0 नहीं, बल्कि एनडीए 3.0 है, जिसका नेतृत्व मोदी कर रहे हैं। इसके पहले दो संस्करणों के नेता वाजपेयी थे। फिर भी भाजपा को हाल के वर्षों में किसी भी सत्ताधारी दल से अधिक सीटें मिली हैं। वर्ष 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 404 सीटें जीती थीं, पर पांच साल बाद वह 197 पर ही जीत सकी। साल 2009 में कांग्रेस

को 206 सीटें मिली थीं। बहरहाल, प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए इस चुनाव ने अनेक प्रश्न खड़े किए हैं और भविष्य में शासन के मॉडल के बारे में निर्देश भी दिया है। पार्टी को अभी यह स्वीकार करना है कि 370 सीटें भाजपा और 400 एनडीए के लिए जीतने का अवास्तविक लक्ष्य नहीं मिल सका है। दक्षिण में भी कुछ अधिक हासिल नहीं हुआ क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सीटों की बढ़त पर कर्नाटक के नुकसान का पानी फिर गया। दो माह के चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री ने 200 से अधिक सभाएं कीं और लगभग 80 इंटरव्यू दिए। लेकिन इन आयोजित कार्यक्रमों से संविधान पर खतरा एवं बढ़ती बेरोजगारी के विपक्ष के नैरेटिव को बेअसर नहीं किया जा सका। साथ ही, निचले स्तर पर चुनाव प्रबंधन के लिए बाहरी एजेंसियों पर अत्यधिक निर्भरता से भ्रम पैदा हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की बहुत कम सक्रियता से भी वोट घटे।

लालकृष्ण आडवाणी ने 2004 में हार के तुरंत बाद कहा था कि भाजपा अपने मुख्य जनाधार की अनदेखी करने के कारण हारी है। आर्थिक नीतियों की कमी भी भाजपा की हार के लिए कुछ जिम्मेदार है। बीते एक दशक में भाजपा सरकार अपनी व्यवसाय समर्थक विचारधारा के बारे में गर्व से बोलती रही है। मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया है। यह जनादेश अच्छी राजनीति और न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था देने के लिए है। जनता को बाजार मॉडल पर बहुत अधिक जोर रास नहीं आया। ऐसा न के बराबर होता है कि शासन के प्रमुख और वरिष्ठ मंत्री लोगों को नतीजों की घोषणा से पहले शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कहें। देश के समूचे स्वास्थ्य को कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई बाजार पूंजी के साथ जोड़ना नीतियों के लिए समर्थन मांगने का एक भ्रामक नैरेटिव है। अधिक से अधिक इससे बड़े कारोबारियों को ही फायदा हो सकता है, इससे लोगों को कुछ हासिल नहीं होता। नेताओं को भविष्य की तैयारी करते समय अतीत से सीखना चाहिए। अगर बाजार के सम्मोहन से राजनीतिक लाभ होता तो नरसिंह राव और मनमोहन सिंह को करारी हार नहीं देखनी पड़ती। अल्पमत की पहली सरकार बनाने वाले राव ने बड़े आर्थिक सुधार लागू किए।

उनके पांच साल के कार्यकाल में शेयर सूचकांक 180 प्रतिशत से अधिक बढ़ा था। पर 1996 में राव हार गए क्योंकि लोगों को लगा कि कांग्रेस अमीरों की पक्षधर है। मनमोहन सरकार के दौर (2004-2014) में सेंसेक्स 400 प्रतिशत बढ़ा था, पर कांग्रेस लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन सकी। स्पष्ट है कि ट्रिकल डाउन (ऊपर से नीचे की ओर) का पश्चिमी पूंजीवादी सिद्धांत भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कारगर नहीं है, जहां 80 करोड़ से अधिक लोग सरकार की मुफ्त योजनाओं पर निर्भर हैं। मोदी के आर्थिक मॉडल में नायडू-नीतीश के सामाजिक समता के मॉडल को भी शामिल करना होगा। अच्छी अर्थनीति आवश्यक रूप से बेहतर राजनीति नहीं होती। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने या खरबपतियों की संख्या में वृद्धि होने से सरकार को मजबूती, भरोसा और स्वीकार्यता हासिल नहीं होती। किसी गठबंधन सरकार की सफलता मुख्य रूप से इस पर निर्भर करती है कि गणित की नई वास्तविकताओं को प्रधानमंत्री किस तरह निभाते हैं। बीते 22 वर्षों में मोदी एक ऐसे प्रशासनिक मॉडल के रूप में स्थापित हुए हैं, जिसमें वे अकेले निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

वे राय मांगते हैं, पर वे सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के अनुरूप नहीं चल पाते। इससे शीघ्र निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में मदद मिली है। वे नारे गढ़ने में भी माहिर हैं। स्वच्छ भारत से लेकर डिजिटल इंडिया तक, अपनी गारंटियों से उन्होंने देश को सम्मोहित किया है। अब तक वे ऐसे मंत्रिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें वे असमान लोगों में प्रथम थे। लेकिन अब नई संख्या और गणित से नीति-निर्धारण निर्देशित होगा। मोदी अभी भी सबसे ताकतवर नेता हैं। उनकी अजेयता को झटका लगा है, लेकिन अभी भी उच्चतम नेता की उपाधि उन्हीं के पास है। देश टकराव नहीं, बल्कि सर्वसम्मति की नयी राजनीति की ओर देख रहा है। केवल यही उपलब्धि उनकी महानता सुनिश्चित कर देगी। नई सरकार को संख्या के बजाय नेकी, खरबपतियों से हाथ मिलाने के बजाय आम जन के स्पर्श तथा निर्देश के बजाय प्रतिनिधित्व की राह पर चलने की आवश्यकता है।

आज का इतिहास

1932 ब्रिटेन और फ्रांस के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।
1935 चैंपियनशिप मुक्केबाजी में सबसे बड़े उतार-चढ़ाव में से एक में, जेम्स जे। ब्रैडॉक ने मैक्स बेयर को हराकर दुनिया का सबसे भारी चैंपियन बन गया।
1952 सोवियत युद्ध के विमानों ने एक स्वीडिश सैन्य डगलस ष्ठ्ट-3-360 स्काईट्रेन को सिग्नल इंटेलिजेंस इकाइयां संचालित करने के लिए गोली मार दी, जिसके बाद कैटालिना फ्लाइंग बोट की शूट डाउन द्वारा तीन दिन बाद स्काईट्रेन की खोज की।
1955 सोवियत भूवैज्ञानिकों ने मीर खदान की खोज की, यूएसएसआर में पहला डियामिनॉन्ड खदान और पूर्वी साइबेरिया में दूसरा सबसे बड़ा खुदाई छेद था।
1956 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (आईसीपीओ) को गठन किया गया।
1956 72 वर्षों तक अपने नियंत्रण में रखने के बाद ब्रिटेन ने स्वेज नहर का नियंत्रण मिस्र को सौंपा।
1963 न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज ने चांदी के वायदा अनुबंधों का कारोबार शुरु किया।
1966 मिरांडा बनाम अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार एरिज़ोना के भूभाग ने मिरांडा चेतावनी की स्थापना की, कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अपने अधिकारों के संरक्षण में एक संदिग्ध को चुप रहने और वकील प्राप्त करने की सलाह दी।
1970 द लॉन्ग एंड विंडिंग रोड संयुक्त राज्य अमेरिका में बीटल्स का बीसवां और अंतिम नंबर का एकल बन गया।
1971 न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन पेपर्स, एक 7,000 पन्नों के शीर्ष-गुप्त संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के इतिहास को वियतनाम युद्ध में राजनीतिक और सैन्य भागीदारी के लिए प्रकाशित करना शुरू किया।
1981 इंग्लिश किशोरी मार्कस सरजेनट ने क्वीनएलीज़बेथ द्वितीय में छह खाली शॉट लगाए क्योंकि वह मॉल ऑफ द ट्रूपिंग द कोलोरिसन में सवार हुई।
1982 फहद सऊदी अरब के बादशाह बने, अपने सौतेले भाई खालिद को बाद की मौत के बाद उत्तराधिकारी बनाया।
1983 पायनियर 10 (पायनियर पट्टिका चित्र) नेपच्यून की कक्षा से गुजरी, सौर मंडल के ज्ञात ग्रहों से परे यात्रा करने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई।

प्रधानमंत्री मोदी से क्यों नाराज है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ?

अजय सेतिया

जिस बात का खंडन किया जा रहा था, या जिस पर बोलने से इंकार किया जा रहा था, वह बात अब खुल कर सामने आ गई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा, भाजपा सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी से बेहद खफा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत या कोई बड़ा पदाधिकारी मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुआ था। अब सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा – सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वह दूसरों को कोई चोट पहुंचाए बिना काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने कहा था कि वह प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हैं।

मोहन भागवत के शब्दों को देखिए- एक सच्चा सेवक काम करते समय मर्यादा बनाए रखता है... जो मर्यादा बनाए रखता है, वह अपना काम करता है, लेकिन अनासक्त रहता है। इसमें कोई अहंकार नहीं है कि मैंने यह किया है। केवल ऐसे व्यक्ति को ही सेवक कहलाने का अधिकार है। मोहन भागवत ने संभवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ ही इशारा करके कहा है कि चुनाव में शिष्टाचार का ध्यान नहीं रखा गया। रविवार को शपथ ग्रहण के बाद अगले दिन जिस समय नई गठबंधन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हो रही थी, ठीक उसी समय मोहन भागवत नागपुर में स्वयंसेवकों के विकास वर्ग के समापन कार्यक्रम में आरएसएस पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे।

चुनावों के दौरान ऐसी कई खबरें आई थीं कि संघ के स्वयंसेवक इस बार भाजपा उम्मीदवारों के लिए पहले जैसी ऊर्जा से काम नहीं कर रहे। ये खबरें कितनी सही थी, कितनी गलत, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद इन खबरों को ज्यादा हवा मिली कि यह संघ की नाराजगी का प्रतिफल है कि भाजपा को महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और हरियाणा में काफी सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। सरसंघचालक मोहन भागवत के इन दो वाक्यों ने इसकी पुष्टि ही की है कि संघ कुछ कारणों से भाजपा से नाराज है।

चुनावों के दौरान ऐसी दो बातें हुई थीं, जिनसे संघ की तथाकथित नाराजगी की खबरें बनी थी। एक तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वह बयान था, जिसे मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया था कि भाजपा संघ पर निर्भर नहीं है, वह सक्षम है, और उसे संघ की जरूरत नहीं है। हालांकि जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। जेपी नड्डा ने कहा था कि – हर किसी का अपना काम है, आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है और भाजपा राजनीतिक संगठन है। शुरुआत में हम कम सक्षम थे और हमें आरएसएस की जरूरत थी। आज हम बड़े हो गए हैं और हम सक्षम हैं, भाजपा खुद को चलाती है, यही अंतर है। दोनों संगठनों में एक दूसरे का बहुत सम्मान है। मीडिया में कुछ लोग आरएसएस और भाजपा संबंधों पर अटकलें लगाना पसंद करते हैं। वे षड्यंत्र के सिद्धांत और मिथक फैलाते हैं। लेकिन उनके इस कथन को अन्य मीडिया ने उसी तरह तोड़मरोड़ कर पेश किया जैसी नड्डा ने आशंका व्यक्त की थी। नड्डा ने यह कभी नहीं कहा था कि भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है।

यह बिलकुल वैसा ही हो गया, जैसे करीब 30 साल पहले दिल्ली के एक हिन्दी दैनिक में छपे एक लेख ने

गोविन्दाचार्य की ओर से अंग्रेजी में कहे गए एक शब्द का हिन्दी रूपान्तर ऐसा कर दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी बुरा मान गए थे। एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल भाजपा मुख्यालय में पार्टी महासचिव गोविन्दाचार्य से मिलने आया था। बातचीत में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ने पूछा कि आप कांग्रेस का विकल्प कैसे बन सकते हैं, जबकि आपके नेता लालकृष्ण आडवानी कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर माने जाते हैं। तो गोविंदाचार्य ने कहा था कि अवर फेस इज ए वेरी लिबरल अटल बिहारी वाजपेयी। यानी पार्टी का चेहरा बहुत ही उदारवादी अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लेकिन लेख में चेहरे की जगह अटल बिहारी वाजपेयी को मुखौटा लिखा गया था। लेकिन मीडिया की ओर से फैलाई गई झूठी खबर का संघ स्वयंसेवकों पर असर नहीं पड़ा होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में दो समुदायों के बीच हुई हिंसा पर भी बोला। विपक्ष ने चुनावों में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझ कर मणिपुर की अनदेखी की। मणिपुर का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा, हर जगह सामाजिक वैमनस्य है, यह अच्छा नहीं है। पिछले एक साल से मणिपुर शांति का इंतजार कर रहा है। पिछले एक दशक से यह शांतिपूर्ण था। ऐसा प्रतीत होता था कि पुराने समय की बंदूक संस्कृति खत्म हो गई थी, लेकिन बंदूक संस्कृति अचानक फिर उभर आई, या उभारी गई।

भागवत ने एक तरह से सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि मणिपुर आज भी जल रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा? इससे प्राथमिकता से निपटना सरकार का कर्तव्य है। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि पिछले सात आठ महीनों से सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही है।

एक और घटना थी, जिस कारण संघ की नाराजगी की अवधारणा को बल मिला। वह घटना यह थी कि भाजपा ने उस कृपाशंकर सिंह को भाजपा में प्रवेश और उत्तर प्रदेश की जौनपुर सीट से लोकसभा का टिकट दे दिया था, जिसने मुम्बई में हुए 26/11 के आतंकी हमले को आरएसएस की साजिश बताया था।

कांग्रेस के कई नेताओं, वामपंथी बुद्धिजीवियों और मुस्लिम कट्टरपंथियों ने यह नेरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि मुम्बई के हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं है। राष्ट्रीय सहारा के उर्दू अखबार रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के संपादक अज़ीज़ बर्नी ने इस पर किताब लिख दी थी, जिसका शीर्षक था- आरएसएस की साजिश 26/11।

मुम्बई में इस किताब का विमोचन कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह, उस समय मुम्बई कांग्रेस के अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह, महेश भट्ट और जमियत उलेमा ए हिन्द के अध्यक्ष महमूद मदनी ने मिल कर किया था। जनवरी 2011 में अज़ीज़ ने अपनी मनगढ़ंत किताब के लिए आरएसएस से माफी मांग ली थी। लेकिन भाजपा ने उसी कृपा शंकर सिंह को भाजपा में प्रवेश दे दिया, जिसने आरएसएस के खिलाफ झूठा नेरेटिव गढने वाली किताब का विमोचन किया था।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चुनावों में इस्तेमाल की गई भाषा और विपक्ष की ओर से बिना वजह आरएसएस को घसीटे जाने से भी क्षुब्ध दिखाई दिए, जब उन्होंने कहा कि चुनावों को एक प्रतियोगिता के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि युद्ध के रूप में। जिस तरह की बातें कही गईं, जिस तरह से दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को आड़े हाथों लिया... जिस तरह से किसी ने भी इस बात की परवाह नहीं की कि किस वजह से सामाजिक विभाजन पैदा हो रहा है।...और बिना किसी कारण संघ को इसमें घसीटा गया...तकनीक का इस्तेमाल कर झूठ फैलाया गया। क्या ज्ञान का उपयोग इसी तरह किया जाना चाहिए? ऐसे कैसे चलेगा देश?

फिर बिना नरेंद्र मोदी या भाजपा के अन्य नेताओं का नाम लिए मोहन भागवत ने कहा कि वह विपक्ष को विरोध पक्ष नहीं कहते, वह इसे प्रतिपक्ष कहते हैं और प्रतिपक्ष विरोधी नहीं होता, प्रतिपक्ष भी एक पक्ष को उजागर कर रहा है और इस पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। भागवत ने कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोनों पहलुओं की जानकारी लेकर ही निर्णय लेने की हमारी परम्परा रही है।

जितनी अधिक सहूलियत, उतना कम मतदान

पंकज चतुर्वेदी

भारत की 18वीं लोकसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही एक सवाल फिर खड़ा हुआ कि आखिर बड़े शहरों में रहने वाले, खासकर संपन्न इलाकों के लोग वोट क्यों नहीं डालते जबकि उनके क्षेत्रों में जन सुविधा-सुंदरता और शिकायतों पर सुनवाई सरकारें प्राथमिकता से करती हैं। गौर करने वाली बात है जो शहर जितना बड़ा है, जहां विकास और जनसुविधा के नाम पर सरकार बजट का अधिक हिस्सा खर्च होता है, जहां प्रति व्यक्ति आय आदि औसत से बेहतर है, जहां सड़क-बिजलीड्डपानी-परिवहन अन्य स्थानों से बेहतर होते हैं। वहीं के लोग वोट डालने निकले नहीं। हरियाणा की दस सीटों में जिन दो जगहों पर सबसे कम मतदान हुआ, वह हैं दिल्ली का

विस्तार कहे जाने वाले-फरीदाबाद और गुरुग्राम हैं। फरीदाबाद में ग्रामीण अंचल की हथिन में 70 फीसदी, पलवल और पर्थला में 65 फीसदी पार वोट पड़े, सो वहां आंकड़ा 60.20 पर पहुंच पाया, वर्ना फरीदाबाद शहर की संभ्रांत बस्तियां कहलाने वाले इलाकों में मतदान 55 से नीचे रहा। गुरुग्राम सीट पर भी नूहं, पुन्हाना, पटौदी, बादशाहपुर जैसे ग्रामीण अंचलों में 65 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। यहां शहर में तो बमुश्किल 55 फीसदी ही वोट गिरे। गाजियाबाद और नोएडा में भी वोट प्रतिशत वहीं ठीक रहा जहां जरूरतमंद लोगों की घनी आबादी है, वरना भरे पेट के मुहल्लों ने तो निराश ही किया। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र को सहेज कर रखने की जिम्मेदारी सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर ही है। इसके बाद भी जब विकास, सौन्दर्यीकरण, नई सुविधा जुटाने की बात आती है तो प्राथमिकता उन्हीं क्षेत्रों को दी जाती है जहां के लोग कम मतदान करते हैं। मतदान को अनिवार्य करना भले ही फिलहाल वैधानिक रूप से संभव न हो लेकिन यदि दिल्ली एनसीआर से यह शुरुआत की जाए कि विकास योजनाओं का पहला हक उन विधान सभा क्षेत्रों का होगा, जहां लोकसभा के लिए सर्वाधिक मतदान हुआ तो शायद अगली बार पॉश इलाकों के लोग मतदान की अनिवार्यता को महसूस कर सकें। राजनैतिक दल कभी नहीं चाहेंगे कि मतदान अधिक हो, क्योंकि इसमें उनके सीमित वोट-बैंक के अल्पमत होने का खतरा बढ़ जाता है। कोई भी दल चुनाव के पहले घर-घर जा कर मतदाता सूची के नवीनीकरण का कार्य करता नहीं और बीएलओ पहले से ही कई जिम्मेदारियों में दबे सरकारी मास्टर होते हैं। हमारा लोकतंत्र भी एक ऐसे अपेक्षाकृत आदर्श चुनाव प्रणाली की बाट जोह रहा है, जिसमें कम से कम सभी मतदाताओं का पंजीयन हो और मतदान तो ठीक तरीके से होना सुनिश्चित हो सके।

यूपी में भाजपा के हिन्दुत्व पर भारी पड़ी सपा की जातीय जुगलबंदी

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यूपी में खराब परफारमेंस की वजह से बीजेपी केन्द्र में अपने दम पर बहुमत का भी आकड़ा नहीं पा कर पाई। भले ही एनडीए के तौर पर उसकी सरकार बनना तय लग है, लेकिन अबकी से उसके सामने चुनौती बड़ी होगी। बीजेपी का यह सारा खेल यूपी ने बिगाड़ा है। 2017 के विधान सभा चुनाव के बाद जिस तरह से अप्रत्याशित तरीके से बीजेपी आलकमान द्वारा योगी को यूपी का सीएम बनाया गया था, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधान सभा चुनाव में मोदी के साथ योगी का भी सिक्का खूब चला। यहां कोई भी चुनाव होता मोदी आगे तो योगी उनके पीछे नजर आते थे। अपने बल पर शानदार प्रदर्शन करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू अबकी लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं चला यह यक्ष प्रश्न है। कहा यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक (पीडीए) फार्मूला ने बीजेपी के हिन्दुत्व को हासिये पर ढकेल दिया। जबकि जमीनी हकीकत यही है कि यूपी की सियासी पिच पर भले योगी मात खा गये हों, लेकिन उनकी सरकार के कामकाज को लेकर किसी को कोई खास नाराजगी नहीं है। आज भी प्रदेश में लॉ एंड आर्डर के कारण उनकी छवि काफी बड़ी दिखती है। विकास के कार्य भी ठीकठाक चल रहे थे, ऐसे में यही कहा जा सकता है कि शायद योगी अपनी बात को मतदाताओं के सामने उतने सही तरीके से नहीं जैसा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव करने में सफल रहे। वहीं बसपा के वोटर को भी जब इस बात का अहसास हुआ कि बहनजी अबकी से रेस में नहीं है तो उसने भाजपा की जगह समाजवादी पार्टी का साथ ज्यादा पसंद किया, यह भी बीजेपी के लिये माइनस प्वाइंट रहा। इसकी वजह भी साफ है। दलित और उसके साथ पिछड़ों को भी इस बात का विश्वास हो गया था कि यदि मोदी मजबूत हुए तो उनका

आरक्षण खत्म हो जायेगा।

बहरहाल, योगी की भविष्य की राजनीति पर लोकसभा चुनाव के नतीजे का प्रभाव पड़ना निश्चित है। एक तरफ विपक्ष उनके खिलाफ ज्यादा हमलावर होगा तो पार्टी के भीतर से भी उनके खिलाफ आवाज उठने लगेंगी। क्योंकि अक्सर ऐसी खबरें आती थीं कि योगी राज में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को कोई महत्व नहीं मिल रहा था और इसकी बड़ी वजह योगी को समझा जाता था। यहां तक की चौकी-थाने तक में बीजेपी नेताओं और पार्षदों की बात तो दूर विधायकों और सांसदों तक की नहीं सुनी जाती थी। यूपी में भाजपा के साथ-साथ उसके सहयोगी दलों को भी झटका लगता है। सुभासपा के बढ़ बोले नेता ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाये तो संजय निषाद की पार्टी का भी एक सीट पर खाता नहीं खुला। हॉ, राष्ट्रीय लोकदल अपनी दो और अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से चुनाव जीत गई हैं। वहीं, सुभासपा को घोसी लोकसभा सीट पर झटका लगा है। इंडिया गठबंधन प्रदेश की 80 में से 43 सीटें जीतने में सफल रहा। इसमें सपा की 37 सीटों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कांग्रेस को भी 6 सीटों पर जीत हासिल हुई, लेकिन इसका श्रेय भी अखिलेश को ही दिया जा रहा है। वहीं, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए 36 सीटों पर ही हासिल कर पाई,जिसमें भाजपा की 33 सीटें थीं। यूपी में उसके सात केन्द्रीय मंत्री चुनाव हार गये। एक सीट पर आजाद समाज पार्टी को जीत हासिल हुई।

दस वर्षो गे बाद अबकी से यूपी के वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिला। भाजपा बड़े स्तर पर पिछड़ी, यह तो सबने देखा, परंतु क्यों पिछड़ी इसको लेकर उसके अंदर भी दुविधा नजर आ रही है। जो बीजेपी 2019 में यूपी में 63 सीटें जीती थीं जो अबकी से वह 33 पर सिमट गई। पार्टी को 30 से सीटों का का नुकसान एठाना पड़ा। वहीं, कांग्रेस का आकड़ा एक से छह पर पहुंच गया है। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़त बनाई है। वहीं, समाजवादी पार्टी अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब रही है। 1992 में समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से अब तक का यह उसका सबसे शानदार प्रदर्शन था। इतना बेहतर प्रदर्शन तो किसी भी लोकसभा चुनाव में स्वयं मुलायम सिंह यादव तक नहीं कर पाये थे। इससे पूर्व 2004 में सपा ने 35 सीटें जीती थीं। इससे यही लगता है कि इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति बेहतर तरीके से जमीन पर उतरने में सफल रही। वहीं, भाजपा के पक्ष में माहौल बनता नहीं दिख पाया। ऐसे में भाजपा प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की रणनीति पर काम कर सकता है। इस पर चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन यह चर्चा हवा-हवाई ज्यादा लगती है।

यह वह चर्चा है जिसे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले हवा दी थी। उन्होंने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में सत्ता परिवर्तन होगा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे। लखनऊ में इंडिया गठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा दावा किया था। केजरीवाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे। उन्होंने मुझे गालियां दीं। योगी

मोदी-शाह की गलतियों का लाभ ममता उठाती रहीं

नीरज कुमार दुबे

लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों के परिणामों ने पूरे देश को चौंकाया है उनमें पश्चिम बंगाल भी शुमार है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ जिस स्तर की नाराजगी देखी जा रही थी। जिस तरह ममता सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों पर घोटाले के आरोप लगे थे। जिस प्रकार संदेशखाली की महिलाओं पर हुआ अत्याचार देश भर में बड़ा मुद्दा बन गया था। जिस प्रकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इर्दगिर्द ईडी का शिकंजा कसा हुआ था। जिस प्रकार ममता बनर्जी को सनातन विरोधी बताया जा रहा था। जिस प्रकार तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने चुनावों से ऐन पहले पाला बदल लिया था। जिस प्रकार मीडिया की सुर्खियों में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ समाचार रिपोर्टें छाई हुई थीं। जिस प्रकार सभी एक्जिट पोलों ने तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान की संभावना जताई थी, उस सबको देखते हुए कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव परिणाम बेहद अप्रत्याशित हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह 30 सीटों का लक्ष्य लेकर अपना चुनाव अभियान आगे बढ़ा रहे थे लेकिन उसका आधा भी हासिल नहीं कर पाये।

यह चुनाव परिणाम दर्शा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की तरह इस बार के लोकसभा चुनावों में भी भाजपा पूरी तरह हवा में ही रही। भाजपा ने मीडिया में हवा बना ली लेकिन जमीनी स्थिति का आकलन नहीं कर पाई। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनावों में 18 सीटें और 2021 के विधानसभा चुनावों में 75 सीटें तो जीत लीं लेकिन पार्टी के नेता जमीन पर लोगों से जुड़ने की बजाय आपस में ही उलझे रहे। दिलीप घोष जैसे वरिष्ठ नेता को लगता रहा कि सुकांत मजूमदार जैसे युवा नेता को पार्टी की कमान क्यों सौंप दी गयी है? कई नेताओं को यह लगता रहा कि तृणमूल कांग्रेस से आये शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा में विपक्ष के नेता जैसा अहम पद तथा तमाम अन्य जिम्मेदारियां क्यों सौंप दी गयी हैं? देखा जाये बंगाल में भाजपा के पुराने और नये नेताओं के बीच सामंजस्य कभी बन ही नहीं पाया और इस दूरी को पार्टी का आलाकमान भी पाट नहीं पाया जिससे भाजपा को बड़ा

नुकसान हो गया। इसके अलावा पार्टी का आलाकमान दिल्ली में बैठ कर बंगाल में पार्टी को चलाता रहा जिसका सीधा असर भाजपा के प्रदर्शन पर दिख रहा है।

इसके अलावा, भाजपा ने लोकसभा चुनावों से पहले सीएए के नियम अधिसूचित कर दिये, यही नहीं बंगाल में मतदान से पहले सीएए के तहत लोगों को नागरिकता भी प्रदान कर दी लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। जिन क्षेत्रों में भाजपा को सीएए का फायदा मिलने की उम्मीद थी वहां भी तृणमूल कांग्रेस जीत गयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों में अपार भीड़ तो उमड़ी लेकिन वह वोटों में परिवर्तित नहीं हो पाई तो इसका एक बड़ा कारण भाजपा की सांगठनिक कमजोरी भी है। भाजपा ने कहने को पार्टी महासचिव सुनील बंसल समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं को बंगाल में लगा रखा था लेकिन परिणाम दर्शा रहे हैं कि यह सभी नेता जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाये। पिछले साल पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनावों में भी भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था लेकिन उसके बावजूद पुरानी टीम को बरकरार रखा गया था। इसके अलावा, ममता बनर्जी जिस तरह सीएए और एनआरसी को लेकर लोगों के बीच भय का वातावरण बनाती रहीं उसकी भी काट भाजपा नहीं कर पाई।

देखा जाये तो ममता बनर्जी की छवि फाइटर नेता की रही है और वह अपनी पार्टी को जिताने के लिए जी-जान लगा देती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान खुद पर होने वाले राजनीतिक हमलों को वह अपने पक्ष में मोड़ लेने में माहिर हैं। इस बार के चुनावों में भी उन्होंने ऐसा कई बार किया। इसके अलावा, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने विभिन्न राज्यों में सीटों का बंटवारा कर आपस में समन्वय बनाकर चुनाव लड़ा लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले ही सारी चुनौती झेली। उनके तमाम नेता भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में थे, भाजपा जैसी साधन संपन्न पार्टी से मुकाबला करना था, इसके बावजूद ममता ने किसी दल का सहयोग नहीं लिया और अपने बलबूते चुनाव प्रचार में उतर गयीं। चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही उनको चोट भी लगी लेकिन इसकी परवाह किये बिना उन्होंने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजेय नेता की छवि उन्होंने तोड़ डाली। मोदी की गारंटी के साथ शुरू हुए भाजपा के प्रचार को ममता के वादों ने धो डाला और बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि वह अपनी दीदी के साथ खड़ी है। इसके अलावा, इन परिणामों ने ममता बनर्जी की क्षेत्रीय नेता की छवि को तो पुख्ता किया ही है साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका महत्व काफी बढ़ा दिया है।

ममता बनर्जी ने जब लोकसभा चुनावों के दौरान एकला चलो का फैसला किया था तब उनको इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने मनाने का प्रयास किया था लेकिन वह नहीं मानी थीं क्योंकि संभवत: उन्हें अपने कामकाज और चुनावी रणनीति पर भरोसा था। आखिरकार ममता का फैसला तब सही साबित हुआ जब लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आये। हम आपको बता दें कि इस बार तृणमूल कांग्रेस के खाते में 29 सीटें गयी हैं जबकि भाजपा के हाथ मात्र 12 सीटें लगी हैं और कांग्रेस को महज एक सीट से संतोष करना पड़ा है जबकि वामपंथी दल एक बार फिर खाली हाथ रह गये हैं। दूसरी ओर, इस चुनाव परिणाम ने ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी का भी कद बढ़ाया है। चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने भी सघन चुनाव प्रचार किया था और ममता के एजेंडे को वह बंगाल में जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं उससे वही टीएमसी प्रमुख के सही राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में नजर आ रहे हैं। चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी और उनकी टीम जिस तरह भाजपा के आरोपों की काट तुरंत-तुरंत करती रही और जोरदार पलटवार करती रही उससे सोशल मीडिया पर खासकर तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिलती रही। बहरहाल, इस चुनाव परिणाम का पूरा दोष मोदी-शाह या नड्डा पर नहीं डाला जा सकता। स्थानीय नेताओं को इस खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेनी होगी खासकर शुभेंदु अधिकारी को। अधिकारी के भाजपा में आने से पहले पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड जीत हासिल की थी।

सपा की साइकिल पर कब तक सवारी करेगी कांग्रेस

अजय कुमार

आम चुनाव में उत्तर प्रदेश से जो नतीजे आये उससे एनडीए गठबंधन का खेल मुश्किल गया, वहीं इंडी गठबंधन को बड़ी सफलता मिली है। इसके चर्चे भी खूब हो रहे हैं। इससे पहले 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में राहुल-अखिलेश का साथ आना और 2019 के लोकसभा चुनाव के समय मायावती-अखिलेश के एकजुट होने की नाकामयाब पटकथा लिखी जा चुकी थी, इसलिए इस बार भी राहुल-अखिलेश की जोड़ी से किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बार तो राहुल-अखिलेश ने चमत्कार दिखाते हुए बीजेपी से आगे-पीछे का सारा हिसाब एक ही बार में बराबर कर लिया। इसके मुख्य किरदार सपा प्रमुख अखिलेश यादव है,जिन्होंने न केवल समाजवादी पार्टी को शानदार जीत दिलाई बल्कि

कांग्रेस को भी यूपी में एक बार फिर से उभरने का मौका दिया, जिसकी वजह से नवगठित मोदी सरकार की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं लग रही है। परंतु सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस गठबंधन का भविष्य कितना लम्बा है। ऐसा इसलिये पूछा जा रहा है क्योंकि चुनाव नतीजे आये कुछ ही दिन नहीं हुए हैं और गांधी परिवार और कांग्रेस यूपी को लेकर नई रणनीति बनाने लगी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की साइकिल पर चढ़कर उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस यदि जल्द सपा की साइकि से उतर कर यूपी की राजनीति में अपना पुराना मुकाम हासिल करने की कोशिश करें तो किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की यह महत्वाकांक्षा भविष्य में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है, क्योंकि तब एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश होगी, जहां से दोनों दलों के बीच सियासी तलवार खींचना निश्चित है। यह सब कब शुरू होगा यह तो निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है लेकिन धीरे धीरे दोनों दलों के बीच दूरियां बढ़ाना शुरू होगी जो अंत में विस्फोटक रूप धारण कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है वह कभी कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक हुआ करता था। कांग्रेस इसे फिर से हासिल करना चाहती है। इस बात के संकेत मिलना भी शुरू हो गए हैं. कहां जा रहा है की यूपी में कांग्रेस को पुरानी प्रतिष्ठा लौटाने के लिए राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी के समझाने पर रायबरेली से ही सांसद बने रहने को तैयार हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस की पहली बैठक और परिवार के साथ रायशुमारी के बाद उन्होंने यह फैसला किया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, राहुल दोनों सीटों में से कौन सी सीट चुनें, उनकी इस दुविधा को सोनिया गांधी ने दूर कर दिया है। सोनिया ने राहुल को समझाया कि यूपी कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए उन्हें रायबरेली अपने पास रखना चाहिए। यह भी कहा जा रहा है कि प्रियंका दोबारा यूपी प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने इस पद को छोड़ दिया था। राहुल के सीट छोड़ने पर प्रियंका वायनाड से उपचुनाव लड़ सकती हैं। गांधी परिवार इसके जरिए उत्तर के साथ दक्षिण में पकड़ मजबूत रखना चाहता है। राहुल के रायबरेली में बने रहने की सहमति के पीछे मां सोनिया की वह भावुक अपील भी है, जिसमें उन्होंने कहा था, 'आपको बेटा सौंप रही हूं।' राहुल ने भी चुनाव नतीजे आने के पहले ही दिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका संकेत दिया था। उन्होंने यूपी को स्पेशल थैंक्यू बोला था।पार्टी के एक सीनियर लीडर ने बताया कि रायबरेली की जीत इस लिहाज से भी बड़ी है कि परिवार ने अमेठी की खोई सीट भी हासिल कर ली है। रायबरेली में राहुल को वायनाड से बड़ी जीत मिली। ऐसे में वह रायबरेली छोड़ेंगे तो यूपी में गलत राजनैतिक मैसेज जाएगा। नेहरू-गांधी परिवार का दशकों पुराना यूपी से रिश्ता भी कमजोर हो जायेगा। क्योंकि गांधी परिवार के मुखिया ने हमेशा यूपी से ही राजनीति की। पिता राजीव गांधी अमेठी और परदादा जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से चुनाव लड़ते रहे हैं। रायबरेली सीट उनकी मां, दादी इंदिरा और दादा फिरोज गांधी की सीट है।

Travelling

में बनाएं करियर, मिलेगा देश-दुनिया भर में घूमने का मौका, करें ये कोर्सेज

एक समय था कि सब को डॉक्टर और इंजीनियर फील्ड में ही जाना पसंद होता था,लेकिन अब दौर बदल चुका है। दरअसल, अब वो स्टीरियोटाइप का दौर लगभग खत्म हो गया है, जहां बच्चों के करियर के लिए उसके पेरेंट्स ही निर्णय लेते थे। आजकल ऐसा नहीं रह गया है। अब बच्चे अपनी पसंद के हिसाब से करियर को चुनते हैं। ऐसे में, आज हम बात कर रहे है कि ट्रैवलिंग में करियर बनाने की। अगर आप घूमने का शौक रखते हैं, तो आप इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं ट्रैवलिंग से जुड़े कोर्सेज के बारे में, जिन्हें आप कर सकते हैं।

ट्रैवल से जुड़े कोर्स क्या-क्या हैं

आप किसी भी विषय में 12वीं पास करने के बाद बीए इन टूरिज्म मैनेजमेंट, बीबीए इन ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बीएससी इन हॉस्पिटैलटी एंड ट्रेवल मैनेजमेंट जैसे कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा, आप टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में पीजीडीएस भी कर सकते हैं। इतनी ही नहीं, आप टूरिज्म में एमबीए कर सकते हैं।

ट्रैवल संबंधित कोर्स के लिए कॉलेज

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ग्वालियर
- जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली दिल्ली
- नेशनल इंस्टूट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हैदराबाद
- केरल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल स्टडीज, तिरुवनंतपुरम
- सेंटर फॉर टूरिज्म स्टडीज, पुडुचेरी
- इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट, थाणे

कोर्स के बाद कैसा होगा करियर

जब आपका टूरिज्म कोर्स हो जाए तो आप किसी भी अच्छी कंपनी से इंटर्नशिप करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इनमें, ट्रेवल एजेंट, टूर गाइड, टूरिज्म मैनेजर, ट्रेलव एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म ऑफिसर, ट्रेवल स्पेशलिस्ट, हॉलिडे एडवाइजर, ट्रेवल कंसल्टेंट, कस्टमर सर्विस मैनेजर आदि शामिल हैं। मार्केट में कई ऐसी कंपनियां हैं, जो टूर पैकेज प्लान करती है। इस फील्ड मे आपके शुरुआती सैलरी के तौर पर 15 से 20 हजार रुपये तक मिल सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर आपकी सैलरी के साथ पोस्ट भी बढ़ेंगे, जिससे आप आगे चलकर लाखों में कमा सकते हैं।

सही जूते-चप्पल का चयन जरूरी है

महिला हो या पुरुष, अपने कपड़ों को लेकर दोनों ही जितने संजीदा रहते हैं फुटवियर के प्रति उतने ही लापरवाह। हम सोचते हैं कि फुटवियर तो हम कोई भी पहन लेंगे। लेकिन उन्हें खरीदते वक्त हम भूल जाते है कि शरीर का पूरा वजन फुटवियर पर ही होता है। तो फुटवियर खरीदने से पहले इन बातों पर ध्यान जरूर रखें।

आमतौर पर कामकाजी महिलाओं और पुरुषों को पूरे दिन फुटवियर पहनना पड़ता है। लिहाजा जरूरी है कि फुटवियर का चुनाव सोच-समझकर ही करें। अगर आपके फुटवियर सही न हों तो यह कमर, घुटनों, पंजों या एड़ी के दर्द का कारण बन सकते हैं। आपका चलना कितना आरामदायक रहेगा यह आपके फुटवियर पर निर्भर करता है। बहुत ज्यादा टाइट और बहुत लूज फुटवियर को पहनकर आप ठीक से नहीं चल पाएंगे, इसलिए फुटवियर पैर के ठीक साइज का हो ताकि आपको चलने में आराम रहे। हाई हील से शरीर पर अनावश्यक भार पड़ता है। इससे पांवों की स्थित एिकदम सीढ़ीनुमा बन जाती है। इससे पैरों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। ऊंची एड़ी के सैंडल लगातार ज्यादा समय तक पहनने से नसों में खिंचाव आ जाता है। लिहाजा इन्हें बीच-बीच में उतारते रहना चाहिए। लेकिन हील वाली फुटवियर कम वजन के लोगों के पहनने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि उन्हें भी हाई हील स्लीपर नहीं पहननी चाहिए। क्योंकि इससे पंजों में दर्द हो जाता है। इसलिए फ्लैट या प्लेटफॉर्म वाली फुटवियर ही पहनें।

स्लीपर खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एड़ी का हिस्सा सॉफ्ट होना चाहिए क्योंकि अगर वह हार्ड होगा तो पैर में दर्द होने का डर बना रहेगा। फुटवियर खरीदते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि वह आगे से ज्यादा चपटी न हो, वरना इससे आपकी उंगलियों में कसाव आने का खतरा बना रहेगा। हालांकि टूटी और घिसी हुई चप्पलें भी दर्द का कारण बन सकती हैं। अगर इन सब दुखों को आप न्योता नहीं देना चाहते हैं तो ऐसा फुटवियर खरीदें जिसमें पूरा पंजा ग्रिप में रहे और दफ्तर से घर लौटने के बाद नमक के गुनगुने पानी में पैर डालकर सिकाई जरूर करें।

अमित भंडारी

मन पर लगाएं लगाम सफलता होगी आसान

सफलता हो या अच्छी सेहत। इन्हें पाने के लिए आत्मनियंत्रण बेहद जरूरी है। पर ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता है कि आत्मनियंत्रण कैसे मजबूत किया जा सकता है। बस इसके लिए 'मन के व्यायाम' की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि कैसे बढ़ा सकते हैं आत्मनियंत्रण।

कमियों को पहचानें

- सबसे पहले उन चीजों को पहचानें, जिनके लुभाने पर आप आत्मनियंत्रण खो बैठते हैं
- इसके जरिए पहले से सोचा जा सकता है कि इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए
- जैसे अगर आपको फिजूलखर्ची की आदत हो, तो पहले से अपने पास कम पैसे रखें

खुद को दें इनाम और सजा

- कुछ करने से रोकने के लिए खुद को इनाम और सजा देने का तरीका होता है अच्छा
- इसके जरिए कुछ समय लुभाने वाली चीजों से दूर रहकर हासिल की जा सकती है सफलता
- जैसे तय करें कि जिस दिन आप धूम्रपान नहीं करेंगे, जाएंगे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने

दिल की सुनें

- दिल हमेशा दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए हमेशा भावनाओं की हिसाब से चलें
- सफलता से मिलने वाले गर्व और रोमांच को महसूस करें, इससे मजबूत बनेंगे आप
- मन को मजबूत बनाएं, इससे बुराइयों से दूर रहने में मिलती है काफी मदद

सकारात्मक सोच

- कई शोधों में पता चला है कि सकारात्मक सोच और कल्पना शक्ति के दम पर भटकाने वाली चीजों से रहा जा सकता है दूर
- जो लोग लक्ष्य को पाने के सपने देखते हैं और समझते हैं कि इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है, वह रहते हैं बुरी लतों से दूर

अचेतन मन से लड़ें

- अक्सर हम लुभावनी चीजों के लिए आत्मनियंत्रण खो बैठते हैं क्योंकि अचेतन मन हमारी मजबूत आकांक्षाओं का करता है विरोध
- भटकाने वाली चीजों से मानसिक और शारीरिक रूप से दूर रहकर और लक्ष्य तक पहुंचाने वाली चीजों के करीब रहने से मिलती है सफलता

इंटीरियर में भी लें एप्लिकेशन की हैल्प

इंटीरियर डिजाइनिंग और होम रिकंस्ट्रक्शन काफी बड़ा काम लगता है। हम आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स के चक्कर काटकर थक जाते हैं। लेकिन अब ऐसी एप्स अवेलेबल हैं, जो आपकी मदद करेंगे। आम तौर पर हम सभी घर के इंटीरियर या एक्स्टीरियर में बदलाव करने से पहले डिजाइनर या फिर आर्किटेक्ट को कंसल्ट करते हैं। लेकिन इन दिनों ऐसी कई एप्स अवेलेबल हैं, जो आपको घर में बदलाव करने में हैल्प करेंगी। ये एप्स कलर स्कीम्स से लेकर फर्निचर सैटिंग तक के लिए आपको गाइड करेंगी।

हाउज

हाउज इंटीरियर डिजाइंस के लिए सबसे पॉपुलर एप है। इस एप में आप घर के इंटीरियर से रिलेटेड कई फोटोग्राफ्स और आर्टिकल्स को सर्फ कर सकते हैं।

होम 3डी

यदि आप घर के फ्लोरिंग या सीलिंग के डिजाइन को लेकर कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो आप होम 3डी एप को डाउनलोड कर हजारों डिजाइन देख सकते हैं।

कलर कैप्चर

कलर कैप्चर भी पेंटिंग से रिलेटेड एप है, लेकिन यह थोड़ी डिफरेंट है। यह एप आपको कलर स्कीम्स के ऑप्शन देने के साथ ही टैक्स्चर डिजाइंस और लोकल पेंटर्स की इन्फॉर्मेशन भी देगी।

कलर स्मार्ट

कलर स्मार्ट आईओएस और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की पॉपुलर एप्लिकेशन है। इस एप को आप आसानी से एप स्टोर या प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप में जब आप अपने घर की दीवारों के फोटो अपलोड करेंगे, तो यह आपको कई कलर स्कीम्स के ऑप्शन देगी। इनमें से आप आसानी से अपने घर के लिए कलर स्कीम पसंद कर सकते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने चंद्रबाबू नायडू

अमरावती। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) चीफ एन. चंद्रबाबू नायडू बुधवार को चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत कई और केंद्रीय मंत्री, मंत्री और नेता शामिल हुए। जनसेना प्रमुख सह अभिनेता पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश समेत अन्य ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने चंद्रबाबू नायडू समेत अन्य को शपथ दिलाई। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा के बाहरी इलाके केसरपल्ली में गन्नावरम हवाई अड्डे के सामने मेधा आईटी पार्क के पास शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह के लिए केसरपल्ली आईटी पार्क को अच्छे से सजयाया गया। वहीं चंद्रबाबू नायडू के बाद जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के मंत्री के रूप में शपथ ली। पवन कल्याण प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हैं।

कांग्रेस ने रियासी हमले पर मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल

नईदिल्ली। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति की वापसी के भाजपा के दावे और खोखले दावे पिछले तीन दिनों में क्षेत्र में हुए तीन आतंकी हमलों से पूरी तरह उजागर हो गए हैं। कांग्रेस नेता और मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने भी इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया और दावा किया कि उनके पास पाकिस्तानी नेताओं को जवाब देने के लिए समय है, लेकिन क्रूर आतंकवादी हमलों की निंदा करने के लिए समय नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के बड़बोलेपन और जम्मू-कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति की वापसी के खोखले दावे पूरी तरह से उजागर हो गए हैं। तथ्य यह है कि भाजपा ने कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ने की जहमत भी नहीं उठाई, यह इस बात का प्रमाण है कि उनका नया कश्मीर है। उनकी टिप्पणी राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि के बीच आई है।

करहल विधानसभा सीट से अखिलेश ने दिया इस्तीफा

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति करेंगे। उन्होंने करहल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वह कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। इसके बाद उन्हें एक सीट से इस्तीफा देना था तो उन्होंने करहल सीट छोड़ दी। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे के अनुसार यह इस्तीफा प्राप्त हो गया है। शीघ्र ही स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इससे पहले सपा के विधायक लालजी वर्मा भी इस्तीफा दे चुके हैं। लालजी वर्मा भी लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ऐसे में आने वाले समय में यह पद उनके चाचा विधायक शिवपाल सिंह यादव या फिर पीडीए के तीन विधायकों रामअचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और कमाल अख्तर में से किसी एक को मिल सकता है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है।

निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला

नईदिल्ली। निर्मला सीतारमण ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए वित्त मंत्रालय का कार्यभार बुधवार को संभाल लिया। वह जल्द ही वित्त वर्ष 2025 के लिए अंतिम बजट पेश करेंगी जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत तीसरी सरकार की प्राथमिकता तथा विकसित भारत की दिशा तय करेगा। नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय में वित्त सचिव टी. वी. सोमनाथन और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने सीतारमण का स्वागत किया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी इस दौरान मौजूद थे। चौधरी ने मंगलवार की शाम को पदभार ग्रहण किया। आधिकारिक बयान के अनुसार, कार्यभार संभालने के बाद वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री को विभिन्न विभागों के सचिवों द्वारा मौजूदा नीतिगत मुद्दों की जानकारी दी गई। सीतारमण ने कहा कि सरकार अपने नागरिकों के ''जीवन की सुगमता'' सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस संबंध में आगे भी कदम उठाती रहेगी।

इलाज के लिए अभिषेक बनर्जी ले रहे हैं राजनीति से छोटा ब्रेक

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी चिकित्सा उपचार के लिए राजनीति से छोटा ब्रेक ले रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को खुद सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही अभिषेक ने लिखा, केंद्र-राज्य संघर्ष में बंगाल के लोग आवास अधिकार से वंचित हैं। तृणमूल ने वादा किया है कि दिसंबर तक इसे पूरा किया जाएगा। अभिषेक ने पोस्ट में बताया कि इसे सुनिश्चित करने का अनुरोध उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से किया है। अभिषेक ने लिखा, मैं इलाज के लिए संगठन से एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। इस दौरान मुझे आम लोगों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलेगा। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार लोगों की समस्याओं का शीघ्र और अच्छे से समाधान करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि लोगों को न्याय मिले।

लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से, सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ

नईदिल्ली। नवगठित 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। संसद के इस विशेष सत्र में लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही लोकसभा के नए स्पीकर का चुनाव भी इसी सत्र के दौरान होगा। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दी है। वहीं राज्यसभा का सत्र 27 जून से होगा और तीन जुलाई तक चलेगा। लोकसभा का सत्र राज्यसभा से तीन दिन पहले शुरू होगा, लेकिन दोनों सदन की कार्यवाही तीन जुलाई को ही समाप्त होगी। संसद के इस सत्र के दौरान राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगी और अपनी सरकार की प्राथमिकता भी बताएंगी।

गौरतलब है कि 18वीं लोकसभा के गठन हो

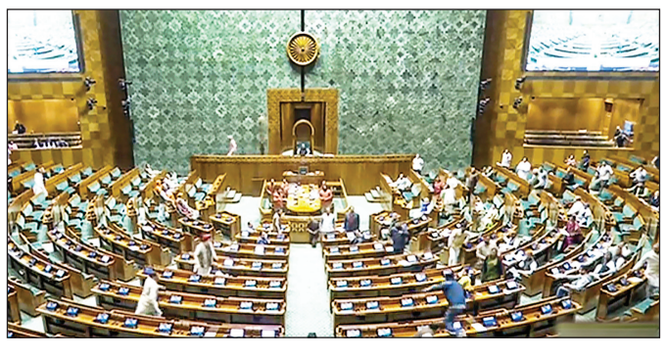

चुका है और चार जून को चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे। नौ जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो चुका है और इस सत्र में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का परिचय दोनों सदन से कराएंगे। साथ ही कुछ मुद्दों पर सदन में चर्चा भी संभव है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में आक्रामक विपक्ष द्वारा विभिन्न मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश किए जाने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक राधा मोहन सिंह, जो सातवीं बार फिर से चुने गए हैं, को सत्र के तीसरे दिन प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुने जाने की उम्मीद थी। पूर्ण केंद्रीय बजट 22 जुलाई को पेश होने की उम्मीद है। इस गर्मी में लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था।

18वीं लोकसभा में कुल 543 सदस्य चुनकार आएं हैं, जिनमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिसके 240 सदस्य चुनकर आएं हैं और उन्हें कुल 63 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जिसे 99 सीटें मिली हैं और पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले में इन्हें 47 सीटों का लाभ हुआ है।

जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नईदिल्ली। दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है। वहीं जल संकट और टैंकर माफिया से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सख्त लहजे में सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि सरकार ने शहर में टैंकर माफिया के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि यदि यदि गर्मियों में जल संकट बार-बार होने वाली समस्या है तो पानी की बर्बादी रोकने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं। दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि आप टैंकर माफिया से नहीं निपट सकते तो हम दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने को कहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुनवाई से पहले आज या कल हलफनामा दाखिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई कल के लिए टाल दी है। गौरतलब है कि दिल्ली में घोर जल संकट है।

नफरत को प्रेम और अहंकार को विनम्रता ने हराया : राहुल

तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को वायनाड पहुंचे थे। राहुल गांधी ने लोकसभा में वायनाड से दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव संविधान की रक्षा के लिए लड़ा गया। उन्होंने कहा कि नफरत को प्रेम ने, अहंकार को विनम्रता ने पराजित कर दिया। उन्होंने कहा कि इस देश का हर एक इतिहास और परंपरा हमारे संविधान द्वारा संरक्षित है।

राहुल ने कहा कि केरल, उत्तर प्रदेश और अन्य सभी राज्यों के लोगों ने प्रधान मंत्री को दिखाया कि वह भारत के लोगों को यह नहीं बता सकते कि वे क्या चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत की जनता भी पीएम से कहती है कि संविधान हमारी आवाज है, इसे मत छुएं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले आपने बीजेपी नेताओं को यह कहते हुए देखा कि वे संविधान को फाड़ देंगे। चुनाव के बाद आपने प्रधानमंत्री को संविधान के साथ ऐसा करते (अपने

माथे से संविधान को छूते हुए) देखा। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि प्रधानमंत्री वाराणसी में बमुश्किल बच पाए और वाराणसी में तो वे खुद ही हार गए होते। अयोध्या में बीजेपी की हार हुई। अयोध्या के लोगों ने संदेश दिया है कि हम नफरत और हिंसा की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली में जो सरकार बनी है वह अपंग सरकार है। आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी को भी अपना रवैया बदलना होगा क्योंकि भारत की जनता ने उन्हें स्पष्ट संदेश दे दिया है। हमने भारत के लोगों के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तावित किया। एक गरीब समर्थक, दयालु दृष्टिकोण और हम उस दृष्टिकोण के लिए लड़ेंगे। हम भारत को एक निष्पक्ष और अधिक उत्पादक समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आतंकी हमले पर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर में श्रद्धालुओं की मौत पर पीएम मोदी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो इस समय बधाई संदेश का जवाब देने में व्यस्त हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त नरेंद्र मोदी को जम्मू-कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिये गए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें तक नहीं सुनाई दे रही हैं। रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिनों में 3 अलग-अलग आतंकी घटनाएं हुई हैं लेकिन प्रधानमंत्री अब भी जश्न में मग्न हैं। देश जवाब मांग रहा है। आखिर भाजपा सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते?

जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमलों पर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अबकी बार वाले कहां गए? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जम्मू-कश्मीर का दौरा नहीं करेंगे? यह उनकी (पीएम मोदी) जिम्मेदारी है, अगर वह इन चीजों को संभाल नहीं सकते, तो उन्हें दोबारा पीएम बनने का कोई अधिकार नहीं है।

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में श्रद्धालुओं की बस पर किए गए हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 41 लोग घायल हुए। आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं को शिव खोरी मंदिर से कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर ले जा रही 53 सीट वाली बस पर पोनी इलाके में तेरयाथ गांव के पास रविवार को गोलीबारी कर दी थी। हमले के बाद बस खाई में जा गिरी थी। वाहन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के श्रद्धालु सवार थे।

कश्मीर से पूरी दुनिया को शांति और धैर्य का संदेश देंगे प्रधानमंत्री

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को श्रीनगर जाएंगे और 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी, जिन्होंने हमेशा योग को दैनिक जीवन में शामिल करने का समर्थन किया है, ने कहा है कि इसने समग्र कल्याण की खोज में दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट किया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोगों से योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की प्रतिबद्धता दोहराने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया।

उन्होंने एक्स पर कहा, अब से 10 दिनों में, दुनिया 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाएगी, जिसमें एकता और सद्भाव का जश्न मनाने वाली एक शाश्वत प्रथा का जश्न मनाया जाएगा। मोदी ने कहा, जैसे-जैसे हम इस वर्ष के योग दिवस के करीब आ रहे हैं, योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना और दूसरों को भी इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। योग शांति का अभयारण्य प्रदान करता है, जो हमें शांति और धैर्य के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। प्रधान मंत्री ने कहा और योग के विभिन्न रूपों और उनके लाभों को दिखाने वाले वीडियो का एक सेट भी साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो शेयर किया है। ये इंटेलिजेंस वर्जन है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी वृक्षासन करते दिख रहे है। इस वीडियो में उन्होंने वृक्षासन के फायदों के बारे में बताया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि वृक्षासन यानी पेड़ की मुद्रा में किए जाने वाले ये आसन बेहद लाभदायक है। इसके कई फायदे है। ये शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने के साथ इसे मजबूती देता है।

खेल
प्रमुख समाचार

कतर से हार के बाद भारत फीफा रैंकिंग में 125वें स्थान पर खिसका

कतर। फीफा विश्व कप क्वालीफायर में मंगलवार को भारत और कतर के बीच हुए मैच में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वह तीसरे दौर के लिए ऐतिहासिक क्वालीफिकेशन हासिल करने से चूक गई। मौजूदा एशियाई चैंपियन कतर ब्लू टाइगर्स के लिए बहुत मजबूत साबित हुआ, उसने दोहा के जसीम बिन हमद स्टेडियम में मैच 2-1 से जीत लिया। फीफा रैंकिंग में 121वें स्थान पर काबिज भारतीय टीम को कतर की उच्च रैंकिंग वाली टीम के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जो वर्तमान में विश्व में 34वें स्थान पर है। अच्छे प्रयास के बावजूद, भारत अपने शुरुआती दबदबे का फायदा उठाने में असमर्थ रहा और अंतत: कतर के अंतिम क्षणों में बढ़त के सामने हार गया।

मैच में भारत के लालियानजुआला चांगटे ने 37वें मिनट में पहला गोल किया, लेकिन कतर की कंसिस्टेंट बॉल पासिंग ने उन्हें 73वें मिनट में यूसुफ अयमेन के माध्यम से बराबरी दिलाने में सफलता दिलाई। इसके बाद अहमद अल-रावी ने 85वें मिनट में गोल करके कतर की जीत पक्की कर दी, जिससे भारत के लिए वापसी करना मुश्किल हो गया।

11 जून 2024 को दोहा के जसीम बिन हमद स्टेडियम में कतर के खिलाफ 1-2 से हार के बाद फीफा विश्व कप 2026 क्वालीफायर में आगे बढ़ने की भारत की उम्मीदें धराशायी हो गईं। इस हार के कारण भारत फीफा रैंकिंग में 125वें स्थान पर आ गया है, जो उसके पिछले कुल 1144.5 से 5.1 अंक कम है, जो अब 1139.4 है।

इस हार के कारण भारत ग्रुप ए में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जिससे विश्व कप क्वालीफायर के राउंड 3 में आगे बढ़ने की उसकी संभावना समाप्त हो गई है। अब उनका ध्यान एएफसी एशियन कप 2027 के तीसरे राउंड क्वालीफिकेशन पर रहेगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 150 अंक चढ़ा निफ्टी 23,300 के पार

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को दो दिन की सुस्ती के बाद एक बार फिर से तेजी लौट आई। ग्लोबल बाजार से मिले मजबूत रुझानों के बीच घरेलू बाजार में बिजली, पूंजीगत उत्पाद और औद्योगिक शेयरों में खरीदारी आने से आज निफ्टी ने अपना उच्चतम स्तर छुआ जबकि सेंसेक्स अपने रिकॉर्ड स्तर से थोड़ा ही दूर रहा। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 149.98 अंक यानी 0.20 फीसदी की हल्की बढ़त के साथ 76,606.57 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 76,533.78 और 77,050.53 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 58.10 अंक यानी 0.25 फीसदी की मामूली बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 23,322.95 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 23,295.95 और 23,441.95 के रेंज में कारोबार हुआ।

तीन साल तक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा भारत

नईदिल्ली। विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में अनुमान जाहिर किया है कि आने वाले तीन सालों में भारत दुनिया भर में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही, उसने यह अनुमान भी जाहिर किया है कि इन तीन सालों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.7 फीसदी पर स्थिर बनी रहेगी। विश्व बैंक की ताजा 'वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट' के अनुसार, भारत में वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि बढ़कर 8.2 फीसदी रहने का अनुमान है। यह विश्व बैंक के जनवरी में जताए गए पिछले अनुमान से 1.9 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही, विश्व बैंक ने वर्ष 2024 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि के 2.6 फीसदी पर स्थिर रहने का अनुमान जताया। उसने कहा कि अगले दो वर्षों में वैश्विक वृद्धि बढ़कर औसतन 2.7 फीसदी तक हो जाएगी। हालांकि, यह भी कारोना महामारी पहले के दशक के 3.1 फीसदी से काफी कम होगी।

प्याज के बढ़ते दाम आम आदमी के निकाल रहे आंसू

नई दिल्ली। देश में प्याज के दामों में एक बार फिर तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 15 दिनों में प्याज के दामों में 30-40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। प्याज के दामों में ये इजाफा कम आवक यानी सप्लाई कम होने के वजह से हो रही है। जबकि ईद उल-अजहा (बकरीद) के आने से पहले प्याज की मांग में जोरदार इजाफा हो चुका है। इस बीच केंद्र सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वो प्याज के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए कुछ जरुरी कदम उठाए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। दरअसल, प्याज के दामों में बढ़ोतरी डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर की वजह से आई है। जून से मंडियों और बाजारों में जो प्याज आ रहा है, वह उस स्टॉक से है जो किसानों और ट्रेडर्स ने रखा हुआ था। इस बीच किसानों को ऐसी आशंका है कि साल 2023-24 की रबी फसल में गिरावट आ सकती है, जिसके बाद उन्हें प्याज के दामों में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

भारत से आईफोन निर्यात 2 बिलियन डॉलर तक पहुंचा

नईदिल्ली। टेक जाइंट कंपनी एप्पल ने भारत से आईफोन के निर्यात पर जोर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों में निर्यात मूल्य 2 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। यह देश के कुल आईफोन उत्पादन (2.6 बिलियन) का 81 प्रतिशत है। मई में, एप्पल ने अप्रैल के समान प्रदर्शन दोहराते हुए फिर से 1 बिलियन डॉलर से अधिक के आईफोन का निर्यात किया। एप्पल के प्रवक्ता ने इस विषय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वित्तीय वर्ष 2025 में तीन एप्पल विक्रेताओं के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत उत्पादन मूल्य 10.2 बिलियन डॉलर (निर्यात सहित) तक पहुंचने का लक्ष्य है। उन्होंने केवल दो महीनों में उस लक्ष्य का 25 प्रतिशत हासिल कर लिया है। अब तक चालू वित्तवर्ष में, एप्पल के प्रमुख विक्रेता Foxconn Hon Hai ने कुल निर्यात का 65 प्रतिशत योगदान दिया है।

बाजार तो ऐसे ही चलता है, इसलिए जरूरी है दीर्घकालीन द्रष्टिकोण

नारायण कृष्णमूर्ति

शेयर बाजारों में निवेश करना कमजोर दिलवालों का काम नहीं है, खासकर तब, जब बाजार अस्थिर हो। जब बाजार एक ही दिन या छोटी अवधि में ऊपर-नीचे होता रहता है, तो इसका मतलब है कि बाजार अस्थिर है। जाहिर है, एक आम निवेशक इस अस्थिरता को चिंता का कारण मान सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमारे दिल की धड़कन ऊपर-नीचे होती रहती है, जो हमें जीवित रखती है, उसी तरह शेयर बाजार के सूचकांक शेयर बाजार को गतिमान रखने के लिए ऊपर-नीचे होते रहते हैं। इस अर्थ में, यदि बाजार का सूचकांक सपाट यानी स्थिर है, तो इसका मतलब है कि यह यानी बाजार मरा हुआ है, ठीक उसी तरह, जैसे दिल की धड़कन रुकने पर कोई व्यक्ति मर जाता है।

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के कई कारक होते हैं, जिनमें स्थानीय एवं वैश्विक समाचार से लेकर राजनीतिक नतीजे, व्यापार चक्र और डर इत्यादि शामिल रहते हैं। फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जिनके कारण शेयर बाजार चरम स्थिति में पहुंच जाता है। विगत चार जून को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आने शुरू हुए थे, तब जिस तरह की चरम स्थितियां देखी गई थीं, वैसी घटना हाल के समय में वर्ष 2021 में कोविड लॉकडाउन की घोषणा के समय देखी गई थी। उस दिन यानी चार जून को, एस ऐंड पी बीएसई सेंसेक्स में 4,000 से अधिक अंकों और लगभग छह फीसदी की भारी गिरावट देखी गई, जो अभूतपूर्व थी। ऐसा लग रहा था, मानो घरेलू और विदेशी, दोनों निवेशक भारतीय बाजारों से बाहर निकलना चाहते थे।

चुनाव परिणाम के दिन भारतीय शेयर बाजार में आई गिरावट पर बात करने से

पहले हमें विगत 19 मई की ओर लौटना चाहिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए कहा था कि चार जून को शेयर बाजार रिकॉर्ड तोड़ देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ही ऐसा कहा था, बल्कि लोकसभा चुनाव के विभिन्न चरणों के दौरान उनके मंत्रिमंडल के कई प्रमुख सदस्यों ने इस तरह की टिप्पणी की थी। सत्तारूढ़ पार्टी के इस आत्मविश्वास को निवेशकों ने बाजार में निवेश करने के संकेत के रूप में समझा। नतीजतन मई के अधिकांश दिनों में, चुनावों के अंतिम चरण तक बीएसई सेंसेक्स ज्यादातर दिनों में बढ़ता ही रहा। इसे इस बात का संकेत माना गया कि बाजार सरकार की वापसी और उसकी नीतियों की निरंतरता में यकीन रखती है। बाजार के लिए जनता के मूड से संकेत लेना और भी दिलचस्प हो गया, क्योंकि एक जून को आए एग्जिट पोल में भाजपा की स्पष्ट और बड़ी जीत की भविष्यवाणी की गई थी।

दरअसल, तीन जून को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 6,851 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने, जिनमें बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और अन्य भारतीय संस्थान शामिल हैं, 1,914 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। हालांकि अगले ही दिन जब मतगणना शुरू हुई, तो चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुईं, खासकर शुरुआती रुझानों में। सरकार गठन को लेकर निवेशकों की चिंता के कारण शेयर बाजार के सेंसेक्स में दिन भर उतार-चढ़ाव देखा गया और यह 4,300 अंक से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुआ। विदेशी निवेशकों ने करीब 1.5 अरब डॉलर के भारतीय शेयर बेचे, जबकि घरेलू निवेशकों ने भी 3,300 करोड़ रुपये से अधिक की बिकवाली की।

बहुत से ऐसे सट्टेबाज थे, जिन्होंने सिर्फ ट्रेंड्स और सुनी गई खबरों के आधार पर ही बाजार में अपना पैसा लगाया था। यह भी संभव है कि इनमें कुछ नए निवेशक भी हों, जो बाजार के जोखिमों को नहीं समझते हों और सिर्फ अटकलों पर ही भरोसा करते हों। उन्होंने भी पैसे गंवाए, क्योंकि उन्होंने बाजार में गिरावट शुरू होते ही डर के मारे अपने पैसे निकाल लिए। अब एक ही दिन में 30 लाख करोड़ रुपये के नुकसान का आंकड़ा बताया जा रहा है। यह जरूरी नहीं कि इनमें से सारा पैसा निवेशकों का ही हो, क्योंकि नुकसान उठाने वालों में कई व्यापारी भी थे, जो बाजार के खिलाफ दांव लगाकर पैसे बनाने के लिए जाने जाते हैं।

विष्णु के सुशासन से
संवर रहा छत्तीसगढ़

सुशासन और समग्र विकास के

माह

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णुदेव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

विकास की नई राह

- कृषक उन्नति से समृद्ध किसान, 3100 रुपए में ख़रीदा धान
- मिला दो वर्षों का 3716 करोड़ रुपए बकाया बोनस
- पीएम आवास से 18 लाख से अधिक परिवारों को अपना मकान, गरीबों का रखा ध्यान
- मुफ्त अनाज से गरीबों का कल्याण, एक करोड़ से अधिक परिवारों को 5 वर्षों तक राशन
- महतारी वंदन से महिलाओं को आर्थिक संबल, प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की मदद से 70 लाख महिलाओं को मिला बल
- तेंदूपत्ता मानदेय अब बढ़कर प्रति मानक बोरा 5,500 रुपए भुगतान, आदिवासी का सम्मान
- शासकीय भर्ती आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिली, युवाओं में चहुँओर खुशी
- भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित, युवा रहेगा अब निश्चिंत
- 'नियद नेल्लानार' से माओवादी समस्या का पूर्ण निदान, लड़ाई से आगे बढ़ विकास का विधान
- त्वरित निर्णय- सख्त प्रशासन, विगत 6 माह में, 129 माओवादी ढेर, 488 गिरफ्तार, 431 आत्मसमर्पण
- 'रामलला दर्शन योजना' से श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा का मिल रहा सौभाग्य

संवाद- 40358/125

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.